17वीं लोकसभा के चुनाव की समीक्षा

(केंद्रीय कमेटी की 7 से 9 जून 2019 तक हुई बैठक में स्वीकृत)

17वीं लोकसभा के जनादेश में भाजपा–नीत एनडीए को 2014 से भी ज्यादा सीटें मिली हैं। भाजपा को 37.4 फीसद वोट मिला है, जो 2014 में मिले 31 फीसद से बढ़ोतरी दर्शाता है। एनडीए का मत फीसद, 2014 के 37.3 फीसद से बढ़कर, 2019 में 43.86 फीसद हो गया है। यह उनके पक्ष में निर्णायक जनादेश है। पिछले पांच वर्षों में भाजपा ने जो दक्षिणपंथी हमला छेड़ा हुआ था, वह इस जनादेश के साथ सुदृढ़ हो गया है।

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों की विपक्षी पार्टियों को छोड़कर, अधिकांश विपक्षी पार्टियों को इन चुनावों में भारी धक्का लगा है।

इन चुनावों में सी पी आइ (एम) तथा वामपंथ को, खासतौर पर केरल, प0 बंगाल तथा त्रिपुरा के अपने गढ़ों में भारी धक्का लगा है। लोकसभा में सी पी आइ (एम) की घटती हुई मौजूदगी, जिसे केंद्रीय कमेटी 2009 से दर्ज करती रही थी, अब भी जारी है और अब लोकसभा में पार्टी की उपस्थिति अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गयी है। मत फीसद के लिहाज से सी पी आइ (एम) के चुनावी प्रदर्शन में गिरावट और पहले शुरू हो गयी थी। 1989 में हमारा वोट 6.6 फीसद था। 2014 तक यह घटकर 3.2 फीसद रह गया था। 2019 में यह 2 फीसद के करीब या उससे भी कम बैठेगा (तालिका–1 देखें)। [चुनाव आयोग ने अब तक हरेक पार्टी के मत फीसद के अंतिम आंकड़े नहीं दिए हैं। इसलिए, यहां दिए गए आंकड़े मीडिया की रिपोर्टों पर ही आधारित हैं।]

भाजपा की निर्णायक जीत

भाजपा ने इस बार 303 सीटें जीती हैं और 2014 की अपनी 282 की गिनती से इजाफा कर लिया है। एनडीए के अपने साझीदारों के साथ मिलकर उसने, 43.86 फीसद वोट लेकर, 353 सीटें जीती हैं।

देश भर में 200 से ज्यादा लोकसभाई सीटों में भाजपा ने 50 फीसद से ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं। गुजरात में सभी 26 सीटों पर, मध्य प्रदेश में 25 सीटों पर, राजस्थान में 23 सीटों पर, कर्नाटक में 20 सीटों पर, दिल्ली में सभी 7 सीटों पर और हरियाणा में कुल 10 में से 7 सीटों पर उसने, कुल डाले गए वोट में आधे से ज्यादा हासिल किए हैं।

जिन राज्यों में कांग्रेस ने विधानसभाई चुनाव के हाल के चक्र में जीत हासिल की थी, वहां भी भाजपा ने झाड़ूमार कामयाबी पायी है। उन विधानसभा चुनावों के बाद, हमारी केंद्रीय कमेटी ने अपने विश्लेषण में कहा था कि हालांकि कांग्रेस ने इन विधानसभाओं में जीत हासिल की है, लेकिन भाजपा के मत फीसद से उसका अंतर बहुत मामूली है। इस आधार पर हमने यह नतीजा निकाला था कि सांप्रदायिक ताकतों द्वारा पेश की जा रही चुनौती बनी हुई है और उनके हमले का तेज होना तय है। अब भाजपा ने इन राज्यों में अपनी स्थिति में और सुधार कर लिया है।

मध्य प्रदेश में भाजपा ने 29 में से 28 सीटें जीत ली हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 11 में से 9 सीटें जीत ली हैं। राजस्थान में भाजपा ने 25 में से 24 सीटें जीती हैं। कर्नाटक में, जहां कांग्रेस का जद (सेकुलर) के साथ गठबंधन है, भाजपा ने 28 में से 25 सीटें जीत ली हैं।

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा एक हद तक दो अन्य राज्यों को छोड़कर, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने ऐसी ही कामयाबी हासिल की है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 62 सीटें ही जीती हैं, पर उसका मत फीसद बढ़ गया है। इसी प्रकार, बिहार में भाजपा-जदयू-रामविलास पासवान की एलजेपी के गठबंधन ने, 40 में से 39 सीटें जीत ली हैं।

उत्तर-पूर्व में भी भाजपा ने कामयाबियां हासिल की हैं। असम में उसने 2014 के मुकाबले दो सीटें ज्यादा जीती हैं और अपनी संख्या 7 से बढ़ाकर 9 कर ली है। अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में भाजपा ने अरुणांचल प्रदेश तथा त्रिपुरा, दोनों में सभी दो-दो सीटें जीत ली हैं। मणिपुर में उसने एक सीट जीत ली है। उसके गठबंधन के सहयोगियों ने मिजोरम, मेघालय, नगालेंड तथा सिक्किम में सीटें जीती हैं।

गुजरात में भाजपा ने सभी 26 सीटों पर कब्जा बनाए रखा है। हिमाचल प्रदेश में उसने सभी 4 सीटें जीत ली हैं। उत्तराखंड में भी भाजपा ने सभी 5 सीटें जीत ली हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन के अच्छा प्रदर्शन करने की सभी प्रत्याशाओं को झुठलाते हुए, भाजपा-शिव सेना ने, 48 में से 41 सीटों पर कब्जा बनाए रखा है।

कांग्रेस की हार

कांग्रेस इन चुनावों में अपने प्रदर्शन में कोई उल्लेखनीय सुधार करने में नाकाम रही है। उसने 52 सीटें जीती हैं और 2014 की अपनी 44 सीटों के मुकाबले अपनी स्थिति सुधारी है। उसने कमोबेश 2014 के चुनाव के बराबर ही मत फीसद बनाए रखा है, जो कुल डाले गए वोट के 20 फीसद के करीब बैठता है।

कांग्रेस पार्टी, चुनावों से पहले विपक्षी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की जिस एकता के लिए अभियान चला रही थी, उसे जमीन पर उतारने में वह विफल रही। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अलग से चुनाव लड़ा। इसका नतीजा यह हुआ कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की एकता नहीं बन पायी। जिन राज्यों में कांग्रेस ने हाल में विधानसभाई चुनाव जीते थे—राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़—उसने अन्य पार्टियों के साथ कोई चुनावी तालमेल करने के लिए प्रयास नहीं किया। हरियाणा और दिल्ली में वह अन्य विपक्षी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ कोई तालमेल करने में विफल रही। इसका नतीजा यह हुआ कि जनता के बीच यह संदेश गया कि विपक्षी पार्टियां, अपने घोषित लक्ष्य के बावजूद एकजुट होने में नाकाम रही हैं। पुन: कांग्रेस ने केरल में वायनाड से अपने अध्यक्ष को लड़ाने का फैसला कर लिया, जिससे यह संदेश गया कि वामपंथ के खिलाफ लड़ाई को, भाजपा और उसके सांप्रदायिक हमले के खिलाफ लड़ाई के मुकाबले ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही थी। प0 बंगाल में भी कांग्रेस ने आखिरकार सी पी आइ (एम) की इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया कि कांग्रेस और सी पी आइ (एम) की सिटिंग सीटों पर, आपस में मुकाबला नहीं हो।

अपने परंपरागत गढ़ों में कांग्रेस पार्टी नुकसान में रही और द्रमुक के नेतृत्ववाले मोर्चे के साझीदार के तौर पर तमिलनाडु में और केरल में, उसने बड़ी बढ़ोतरी दर्ज करायी।

कांग्रेस ने, धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में जिस रूप में प्रतिष्ठापित है, उसकी हिफाजत करने के लिए कारगर अभियान नहीं चलाया। इस पहलू से विचारधारात्मक हमला गायब ही रहा। उल्टे उसके अनेक नेताओं ने, पार्टी अध्यक्ष द्वारा मंदिरों में जाकर दर्शन करने के अपने कार्यक्रमों को प्रचारित किए जाने से लेकर, साधुओं को प्रचार के लिए इकट्ठा किए जाने तक (जैसे भोपाल में) के जरिए, भाजपा के सांप्रदायिक हमले के खिलाफ विचारधारात्मक लड़ाई की धार कुंद कर दी। नरम हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व का जवाब नहीं हो सकता है। विचारधारात्मक लड़ाई तो हिंदुत्व और धर्मनिरपेक्षता के बीच है।

इस तरह कांग्रेस खुद को विकल्प के रूप में पेश करने में विफल रही।

भाजपा का प्रचार अभियानः

एक अंध-राष्ट्रवादी सांप्रदायिक चुनावी आख्यान

दक्षिणपंथ की ओर झुकाव का सुदृढ़ीकरणः ये नतीजे भारत में दक्षिणपंथ की दिशा में राजनीतिक झुकाव के, जिसे हमने अपनी 22वीं कांग्रेस में दर्ज किया था, और सुदृढ़ीकरण के सूचक हैं। यह पार्टी कांग्रेस के प्रस्ताव में दर्ज किए गए अंतर्राष्ट्रीय रुझान के अनुरूप है, जिसके तहत पूंजीवाद के प्रदीर्घ संकट से पैदा होने वाले हालात के जवाब में, दुनिया के अनेक देशों में राजनीतिक दक्षिणपंथ का सुदृढ़ीकरण हो रहा है।

चुनावी आख्यान बदल दियाः पुलवामा के आतंकी हमले और उसके बाद हुए बालाकोट के हवाई हमले का भाजपा ने जमकर दोहन किया और हिंदुवावादी राष्ट्रवाद के गिर्द और उन्माद जगाने वाला अभियान छेड़ा। इसने उसके चुनावी प्रदर्शन में जबर्दस्त उछाल ला दिया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को भारत के रखवाले के तौर पर पेश किया जा रहा था, जबकि जमीनी सचाइयां इससे बिल्कुल अलग थीं। पिछले पांच वर्षों के दौरान आतंकी वारदातों में बहुत भारी बढ़ोतरी हुई थी। 2009-14 की तुलना में, 2014-19 के दौरान, आतंकवादी हमलों की संख्या 109 से बढ़कर 626 हो गयी; मारे गए सुरक्षाकर्मियों की संख्या 139 से बढ़कर 483 हो गयी; मारे गए नागरिकों की संख्या 12 से बढ़कर 210 हो गयी और युद्धविराम उल्लंघनों की संख्या 563 से बढ़कर 5596 हो गयी।

इस सचाई के विपरीत भाजपा इन चुनावों में चुनावी आख्यान को रोजी-रोटी के उन अनेकानेक मुद्दों से दूर ले जाने में कामयाब रही, जिनके चलते पिछले पांच साल में जनता को बदहाली झेलनी पड़ी थी। कृषि संकट, नोटबंदी, बढ़ती बेरोजगारी, मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म क्षेत्र (एमएसएमई) पर जीएसटी का सत्यानाशी प्रभाव तथा इसके चलते रोजगार की हानि, समग्रता में अर्थव्यवस्था गतिरोध जिसके चलते जनता पर अनेकानेक बोझ लादे गए हैं, महंगाई, आदि सब के सब महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। लेकिन, इन सभी मद्दों को एक ऐसा आख्यान गढ़ने के जरिए पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया, जो आख्यान सांप्रदायिक राष्ट्रवादी उन्माद के गिर्द खड़ा किया था और जिसमें पिछले पांच साल में चलाए जाते रहे घर वापसी से लेकर लव जेहाद, गोरक्षा आदि तक के अभियान मदद कर रहे थे। ये अभियान अल्पसंख्यकों के और खासतौर पर मुसलमानों तथा दलितों को निशाना बनाकर, हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक वोट बैंक को

पुख्ता करने का प्रयास करते थे।

आतंकवाद का मुद्दा: चुनाव के दौरान भाजपा के सांप्रदायिक प्रचार अभियान के आख्यान के साथ-साथ, आतंकवाद के मुद्दे को उछाला जा रहा था और बताया जा रहा था कि कैसे देश को एक ऐसी सरकार तथा नेतृत्व की जरूरत है, जो सीमा के पार पाकिस्तान से होने वाले आंतकवादी हमलों से देश की रक्षा करने में समर्थ हो। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को, 'हिंदू' भारत की रक्षा करने तथा 'मुस्लिम' पाकिस्तान के खिलाफ अभियान के तौर पर पेश किया जा रहा था। इसने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को पुख्ता करने में मदद की। अंतिम विश्लेषण में यही आख्यान चुनावी विमर्श पर हावी रहा, जिसमें नरेंद्र मोदी को भारत की हिफाजत करने के 'झंडाबरदार' के तौर पर पेश किया जा रहा था। पुलवामा का आतंकवादी हमला और बाद में हुआ बालाकोट आतंकवादी हमला, आरएसएस-भाजपा द्वारा खड़े किए गए इस भावनात्मक अभियान में महत्वपूर्ण तत्व बन गए।

सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सुदृढ़ीकरण: पिछले पांच साल से चल रहा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का हमला, इस जनादेश के साथ सुदृढ़ हो गया है। इन पांच वर्षों के दौरान आरएसएस की सुव्यवस्थित तरीके से सभी संस्थाओं में घुसपैठ करायी गयी है। शिक्षा संस्थाओं खासतौर पर उच्च शिक्षा की संस्थाओं, शोध संस्थानों तथा सांस्कृतिक अकादमियों का, आरएसएस के लोगों द्वारा व्यवस्थित तरीके से अधिग्रहण किया गया है। इसके साथ ही साथ संवैधानिक सत्ताओं को और सीबीआइ, आरबीआइ, सीवीसी, सीआइसी आदि स्वतंत्र एजेंसियों के कमजोर किए जाने ने, सांप्रदायिक हिंदुत्ववादी हमले के सुदृढ़ीकरण की इस प्रक्रिया में मदद की है। हाल में संपन्न चुनाव में चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण भूमिका, इस तरह के प्रयासों के चरमोत्कर्ष को दिखाती है।

मोदी की छवि का निर्माण: आख्यान के इस तरह बदले जाने में मोदी की एक अतिमानवी छवि के गढ़े जाने ने भारी मदद की। यह दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि देश का नेतृत्व करने के लिए, मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है। भाजपा ने नरेंद्र मोदी पर केंद्रित एक राष्ट्रपति प्रणाली के ढंग का चुनाव अभियान चलाया था। उसने जनता से अपील की थी कि अपने=अपने चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवार को भूलकर, सीधे नरेंद्र मोदी के लिए वोट डालें। इस तरह की हवा अनेक कारकों के योग के जरिए बनायी गयी थी। पहली बात तो यह कि भाजपा ने प्रौद्योगिकीय सहूलियतों का और संचार व संवाद प्रेषण के नये औजारों का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इन प्रौद्योगिकीय सहायक उपकरणों के उपयोग को, बिग डॉटा एनालिटिक्स की मदद हासिल थी, जो व्यक्ति विशिष्ट जानकारियां मुहैया कराते हैं, ताकि व्हाट्सएप, फेसबुक

तथा अन्य प्लेटफार्मों के जरिए, उन्हें व्यक्ति-विशिष्ट संदेश दिए जा सकें। चुनाव के बाद भाजपा ने इसकी शेखी मारी थी कि वह, व्यक्ति विशिष्ट संदेश-प्रेषण के जरिए, करीब 25 करोड़ व्यक्तियों तक, उनकी अपनी भाषाओं/ बोलियों में पहुंचने में कामयाब रही थी। इस तरह के विस्तारित संपर्क का निशाना युवा और खासतौर पर पहली बार के मतदाता थे।

सर्वव्यापी हिंदुत्ववादी पहचान: चुनाव अभियान के दौरान भाजपा-आरएसएस ने एक ऐसी सर्वव्यापी हिंदू पहचान गढ़ी थी जो एक हद तक जनता के बीच मौजूद सामाजिक व इथनिक विभाजनों को पार करती थी। इसके साथ ही माइक्रो-स्तर पर सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लिया गया था ताकि कुछ राज्य में खड़े किए गए प्रभुत्वशाली जातियों पर आधारित सामाजिक गठबंधनों की सफलता के साथ काट की जा सके। भाजपा ने गैर-प्रभुत्वशाली जातियों तथा अलग-अलग आदिवासी समुदायों को निशाना बनाते हुए, उनके लिए विशेष रूप लछित संदेश दिए थे तथा लक्षित प्रचार किया था। इसके साथ ही साथ, आरएसएस तथा उसके ताने-बाने ने मतदाताओं से सीधे संपर्क किया था और उन तक भाजपा की पहुंच को पुख्ता किया था।

केंद्रीय योजनाएं: ऐसा लगता है कि निजी तौर पर प्रधानमंत्री के नाम से घोषित की गयीं अनेक सरकारी योजनाओं का भी, जनता के कुछ हिस्सों के बीच कुछ असर हुआ है। किसानों के लिए सीधे धन के हस्तांतरण, शौचालयों के निर्माण, रसोई गैस सिलेंडर योजना आदि का लाभ हो सकता है कि उतने लोगों तक न पहुंचा हो, जितने का सरकार के प्रचार में दावा किया जा रहा था, फिर भी उनके चलते भाजपा को समर्थन मिला लगता है।

कार्पोरेटी धन और मीडिया की विराट शक्ति

बेशक, ये कोशिशें इसीलिए संभव हुईं कि भाजपा ने पिछले पांच सालों के दौरान संसाधनों पर बहुत भारी नियंत्रण हासिल कर लिया था। इसमें भारतीय बड़े पूंजीपतियों से पूरी-पूरी मदद मिल रही थी, जिन्हें दरबारी पूंजीवाद के उस नग्नतम रूप का फायदा मिला था, जैसा रूप इससे पहले कभी देश ने नहीं देखा था। इन चुनावों में विराट धनशक्ति का इस्तेमाल कर, कार्पोरेट मीडिया को उनके आख्यान को प्रचारित करने के लिए जोता गया था। चुनाव के नतीजे के बाद, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने यह अनुमान लगाया है कि इस चुनाव में भाजपा ने पूरे 27,000 करोड़ रु0 खर्च किए थे यानी चुनाव पर हुए कुल खर्चे के 45 फीसद के बराबर। चुनावी बांडों

के जरिए फंडिंग ने विकट रूप ले लिया है। इसी साल जनवरी और मई के बीच, बांडों के जरिए कुल 4794 करोड़ रु0 दिए गए हैं। यह बात खासतौर पर गौर करने वाली है कि मई के महीने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 822 करोड़ रु0 के जो बांड बेचे गए थे, उनमें से 370 करोड़ रु0 यानी कुल रकम के 45 फीसद के बांड, कोलकाता मेन ब्रांच द्वारा ही बेचे गए थे। इन कार्पोरेट संसाधनों का ज्यादातर हिस्सा भाजपा के ही खातों में पहुंचा है। कार्पोरेट फंडिंग के ऐसे पूरी तरह से असंतुलित पैटर्न के साथ, बराबरी के अवसर की शर्त, जो कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है, एक असंभव बात ही होती जा रही है। **चुनावी बांड योजना को तो निरस्त किया जाना ही चाहिए।**

भाजपा, आरएसएस के संगठनों के ताने-बाने के जरिए, तीन साल से बड़े व्यवस्थित तरीके से उम्मीदवारों की पहचान करने, मतदान केंद्र स्तर पर कमेटियां स्थापित करने, लाखों की संख्या में सवेतन वालंटियर तैनात करने और व्यक्ति-व्यक्ति से संपर्क करने में लगी हुई थी। घर-घर तक पहुंचने के अभियानों के साथ-साथ उसके वालंटियरों द्वारा, सरकारी योजनाओं के माध्यम से, गुजारा सहायता लाभ भी मुहैया कराए जा रहे थे।

इन तमाम प्रयासों के फलस्वरूप भाजपा एक ऐसा वैकल्पिक आख्यान गढ़ने में सफल रही, जिसने जनता की रोजी-रोटी के गंभीर चिंताओं को पीछे धकेल दिया। और मोदी की छवि के प्रचार ने यह सुनिश्चित किया कि ऐसा कोई विकल्प नहीं रह गया जो राष्ट्रीय स्तर पर वहनीय दिखाई देता।

सत्ताधारी वर्गों का समर्थन

बड़े कारोबारियों तथा कार्पोरेटों के प्रचंड रूप से बड़े हिस्से ने इस चुनाव में भाजपा तथा नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया था। भाजपा की सरकार पिछले पांच साल से जिस भीषण दरबारी पूंजीवाद पर चल रही थी, उसके चलते भीमकाय कार्पोरेट खिलाड़ियों की दौलत में भारी बढ़ोतरी हुई थी। कुछ मिलालें ली जा सकती हैं। 2014 से 2018 के बीच, मुकेश अंबानी के औद्योगिक साम्राज्य की दौलत दोगुनी हो गयी है यानी 23 अरब डालर से बढ़कर 55 अरब डालर। इसका अर्थ है कि भाजपा के राज के पांच साल में मुकेश अंबानी ने जितनी दौलत बटोरी है, उतनी दौलत तो मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले के 58 साल के अपने पूरे जीवन में उसने नहीं बटोरी थी, जिसमें विरासत में मिली दौलत भी शामिल है।

गौतम अडानी के अडानी एंटरप्राइजेज ने गुजरात में मोदी के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए, अपनी परिसंपत्तियों में पूरे 5,000 फीसद की बढ़ोतरी की थी। और 2014 से 2018 तक, चार साल में अडानी की कुल दौलत 2.6 अरब डालर से चार गुनी से ज्यादा बढ़कर, 11.2 अरब डालर पर पहुंच गयी।

इसी अवधि में रामदेव का उद्योग पातंजलि, एक अपेक्षाकृत छोटे पैमाने के धंधे से बढ़कर, अरब डालर की कंपनी बन गया। 2018 में उसकी कुल दौलत 6 अरब डालर से ज्यादा हो गयी। रामदेव, भारत के 20 सबसे धनवानों में से एक है।

इस तरह के दरबारी पूंजीवाद ने अपने चुनाव अभियान के लिए भाजपा को विराट पैमाने पर संसाधन मुहैया करा दिए। हजारों करोड़ रु0 विज्ञापनों पर और पेड न्यूज पर खर्च किए गए। कार्पोरेट मीडिया का इस्तेमाल और इलैक्ट्रोनिक संदेश वितरण, सभी कुछ विराट पैमाने पर किया गया। अवैध रूप से नमो टीवी के चलाए जाने से (जिसे चुनाव आयोग ने चलने दिया) नरेंद्र मोदी की एक अतिकाय छवि के निर्माण में मदद मिली। इस प्रचार आंधी का आम तौर पर जनता पर और खासतौर पर युवाओं पर असर पड़ा।

चुनाव आयोग

संघ-भाजपा को अपना उक्त वैकल्पिक आख्यान और मोदी की छवि गढ़ने देने में, चुनाव आयोग ने भी एक भूमिका अदा की। चुनाव आयोग की यह भूमिका, भारतीय जनतंत्र के लिए अनिष्टकर है।

इन चुनावों का अनुभव स्पष्ट रूप से इसके अत्यावश्यक होने को रेखांकित करता है कि दूरगामी चुनाव सुधार किए जाएं और चुनाव आयोग में ही सुधार किया जाए।

तत्कालीन सरकार द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किए जाने का अब तक जो तरीका चला आ रहा है, उसकी जगह पर ऐसी व्यवस्था लायी जाए जिसमें राष्ट्रपति के अनुमोदन से, एक कॉलीजियम द्वारा ये नियुक्तियां की जाएं।

सी पी आइ (एम) ने अपने चुनाव घोषणापत्र में देश में जनतंत्र को मजबूत करने के लिए, चुनाव सुधारों के मुद्दे को रेखांकित किया था। जहां तक ईवीएम मशीनों की निष्पक्षता को लेकर विभिन्न शिकायतों का और इन मशीनों के साथ छेड़छाड़ संभव होने की आशंकाओं का सवाल है, सी पी आइ (एम) ऐसी रिपोर्टों का अध्ययन करेगी और अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ परामर्श कर, आगे की कार्रवाई की दिशा तय करेगी।

आने वाली दिनों में सी पी आइ (एम), इसमें साथ आने के लिए तैयार अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर, इस तरह के चुनाव सुधारों के लिए अभियान तेज करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे चुनावों में, सच्ची भावना के अनुरूप जनतंत्र को मजबूत किया जाए।

सी पी आइ (एम) की चुनावी कार्यनीतिक लाइन

22वीं कांग्रेस की राजनीतिक लाइन के आधार पर, केंद्रीय कमेटी ने अपनी 2018 के अक्टूबर की बैठक में, 17वीं लोकसभा के चुनाव में लागू किए जाने के लिए सी पी आइ (एम) की चुनावी कार्यनीति सूत्रबद्ध की थी। केंद्रीय कमेटी ने दर्ज किया था:

''इस चुनाव में मुख्य काम निम्नलिखित लक्ष्य हासिल करना है:

''अ) भाजपायी गठजोड़ को हराना;

''ब) लोकसभा में सी पी आइ (एम) तथा वामपंथ की ताकत बढ़ाना; और

''स) यह सुनिश्चित करना कि केंद्र में एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन हो।

''भाजपा का मुकाबला करने के लिए कोई अखिल भारतीय गठबंधन नहीं बन सकता है। इसलिए हमें समग्रता में चुनावी कार्यनीतिक लाइन के आधार पर राज्यवार चुनावी कार्यनीति तय करनी होगी। हमें विभिन्न राज्यों में धर्मनिरपेक्ष तथा जनतांत्रिक ताकतों को गोलबंद करना होगा ताकि भाजपा तथा उसके सहयोगियों को हराने के लिए ताकतों की व्यापकतम गोलबंदी की जा सके।

''हमें, भाजपायी गठजोड़ के खिलाफ लड़ने वाली गैर-कांग्रेसी धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रीय पार्टियों के साथ तालमेल के लिए प्रयास करना चाहिए।...

''राजनीतिक प्रस्ताव में ध्यान दिलाया गया है कि हमारी लाइन, भाजपा और कांग्रेस के बीच समान दूरी की नहीं है। इसलिए, जिन राज्यों में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है (मिसाल के तौर पर **गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश** तथा अन्य राज्य) हमें सिर्फ एक-दो सीटें लड़नी चाहिए और आम तौर पर भाजपा को हराने के लिए प्रचार करना चाहिए।''... और हम

''अपनी राजनीतिक समझ के आधार पर, भाजपा-विरोधी वोट की एकता को अधिकतम करने में योग दे सकते हैं।''

चुनाव के नतीजे आने के बाद यह स्पष्ट है कि हमने जिन तीन कामों को अपने चुनाव अभियान का आधार बनाया था, उनमें से एक को भी पूरा नहीं कर पाए हैं। महाराष्ट्र में ढिंढोरी सीट के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और बिहार में उजियारपुर के लिए राजद से तालमेल की हमारी कोशिश सफल नहीं हो पायी। तमिलनाडु अकेला राज्य है जहां क्षेत्रीय पार्टियों के साथ तालमेल हो पाया और यहां हमने दो सीटें लड़ीं तथा दोनों जीत लीं।

सी पी आइ (एम) का प्रदर्शन

केरल

केरल में इस चुनाव में सी पी आइ (एम) को धक्का लगा है। राज्य की लोकसभा की 20 सीटों में से पार्टी तथा एलडीएफ को एक ही सीट मिली है। अपनी कई मजबूत सीटों पर पार्टी हार गयी है। पार्टी को ऐसा ही धक्का इमर्जेंसी के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में लगा था, जब उसे एक भी सीट नहीं मिली थी।

एलडीएफ का मत फीसद 2014 के 40.2 फीसद से गिरकर, 2019 में 35.1 फीसद रह गया है, जो 5.1 फीसद की गिरावट को दिखाता है। एलडीएफ को पड़े वोटों की संख्या 2014 के 72,11,257 घटकर, 2019 में 71,56,387 पर आ गयी है यानी उसके वोट में 54,870 की कमी हुई है। यूडीएफ को 2014 में 42.04 फीसद वोट मिला था, जो 2019 में बढ़कर 47.23 फीसद हो गया यानी 5.19 फीसद बढ़ गया। यूडीएफ का वोट 2014 के 75,46,830 के आंकड़े से बढ़कर 2019 में 96,28,034 हो गया यानी उसमें 20,81,204 की बढ़ोतरी हो गयी। एनडीए का मत फीसद, 2014 के 10.8 फीसद से बढ़कर 2019 में 15.56 फीसद हो गया यानी 4.76 फीसद बढ़ गया। एनडीए का वोट, 2014 के 19,44,204 से बढ़कर, 2019 में 31,71,738 हो गया यानी उसमें 12,27,534 की बढ़ोतरी हो गयी। इस तरह, जहां एलडीएफ के वोट में 54,870 की कमी हो गयी, यूडीएफ के वोट में 20,81,204 की और एनडीए के वोट में 12,27,534 की बढ़ोतरी हो गयी।

2019 के चुनाव में 2014 के मुकाबले 3.48 फीसद वोट ज्यादा पड़े थे यानी कुल पड़े हुए वोटों में 24,32,861 की बढ़ोतरी हुई थी।

2016 के विधानसभाई चुनाव में एलडीएफ का वोट 43.35 फीसद (87,25,934) रहा था, जबकि यूडीएफ को 38.8 फीसद (78,08,743) और एनडीए को 15.01 फीसद (30,20,886) वोट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव की तुलना में,

2019 में 0.33 फीसद (2,54,758) ज्यादा वोट पड़े हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एलडीएफ के वोट में, 2016 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 15,69,973 की कमी हो गयी। दूसरी ओर, इन्हीं दो चुनावों के बीच यूडीएफ के वोट में 18,19,291 और एनडीए के वोट में 1,50,852 की बढ़ोतरी हुई। कुल 140 विधानसभाई क्षेत्रों में से, एलडीएफ को सिर्फ 16 विधानसभाई क्षेत्रों में बढ़त हासिल हुई, जबकि यूडीएफ को 123 विधानसभाई क्षेत्र में और एनडीए को 1 विधानसभाई क्षेत्र में बढ़त हुई, जहां पिछले विधानसभाई चुनाव में उसे जीत हासिल हुई थी।

केरल में लोकसभा चुनाव में मतदान का पैटर्न हमेशा से विधानसभा चुनाव के पैटर्न से भिन्न रहता आया है। इस बार, भाजपा और नरेंद्र मोदी के दोबारा केंद्र में सरकार बनाने की आशंका से, धर्मनिरपेक्ष तथा जनतांत्रिक विचारवाले तबकों के बीच और खासतौर पर मुस्लिम तथा ईसाई अल्पसंख्यकों के बीच, यूडीएफ के पक्ष में और भारी झुकाव आया। इस झुकाव में, केंद्र में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने और कांग्रेस को लोकसभा में अकेले सबसे बड़ी पार्टी बनाने के यूडीएफ के प्रचार अभियान ने और मदद की। इस प्रभाव को और बढ़ाने के लिए ही राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया था।

अखिल भारतीय स्तर पर पार्टी तथा वामपंथ के कमजोर होने और खासतौर पर पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा की हारों के चलते, हमारा यह नारा जनता के बीच ज्यादा भरोसा नहीं जगा सका कि संसद में वामपंथ की ताकत बढ़ायी जाए ताकि वामपंथ केंद्र में धर्मनिरपेक्ष सरकार के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके।

सबरीमला मंदिर में हर आयु की महिलाओं के प्रवेश की इजाजत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में, पार्टी तथा एलडीएफ सरकार ने दृढ़ रुख अपनाया था। पार्टी तथा एलडीएफ सरकार ने जो रुख अपनाया, सही था। पार्टी और एलडीएफ सरकार का, सुप्रीम कोर्ट के लैंगिक समानता सुनिश्चित करने वाले फैसले का साथ देने के सिवा दूसरा कोई रुख हो भी नहीं सकता था। लेकिन, श्रद्धालुओं के एक हिस्से के बीच इस पर पैदा हुए विभ्रम का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस, आरएसएस और भाजपा ने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करने के अपने पहले के रुख से पल्टी मारी और इसे लेकर पार्टी तथा एलडीएफ सरकार के खिलाफ भीषण अभियान छेड़ दिया। वे हमारे परंपरागत समर्थकों के एक हिस्से को हमसे दूर करने में कामयाब हुए। महिला प्राचीर कार्यक्रम के बाद, दो महिलाओं के मंदिर में प्रवेश का भी, यूडीएफ और भाजपा ने इस्तेमाल किया। इस अभियान से हमारे समर्थकों पर अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग हद तक असर हुआ। इसे लेकर हमसे अलग हुए

लोगों ने अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों में, अलग-अलग तरीके से कांग्रेस या भाजपा को वोट दिया।

सी पी आइ (एम) तथा वामपंथ के हरवाने के लिए, भाजपा केरल में ही हमेशा ही अपने वोट का एक हिस्सा यूडीएफ को हस्तांतरित करती आयी है। इस बार भी, पांच सीटों—तिरुअनंतपुरम, अट्टिंगल, पत्तनमथिट्टा, त्रिशूर तथा पलक्काट—को छोड़कर, भाजपा ने अपने वोट का एक हिस्सा यूडीएफ को हस्तांतरित कराया था।

कुल मिलाकर, एलडीएफ सरकार के प्रदर्शन की लोगों के बीच काफी सराहना हो रही है। हम जनता के इस सराहना के भाव को एलडीएफ के लिए चुनावी समर्थन में तब्दील करने में क्यों विफल रहे, यह ऐसा विषय है जिस की छानबीन करनी पड़ेगी और उन क्षेत्रों की पहचान करनी पड़ेगी, जिनमें उपचारात्मक कदम उठाए जाने की जरूरत है।

यूडीएफ, भाजपा और प्रभुत्वशाली मीडिया ने हमारी पार्टी के खिलाफ भीषण प्रचार अभियान चलाया था कि अकेले वही केरल में राजनीतिक हिंसा के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, राजनीतिक हिंसा की ज्यादा झोक सी पी आइ (एम) को ही झेलनी पड़ी है, यूडीएफ, भाजपा और मीडिया, हमारी पार्टी की छवि बिगाड़ने के लिए कुछ घटनाओं का इस्तेमाल करने में कामयाब रहे। पार्टी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे विरोधियों को इसका कोई मौका ही नहीं मिले कि वे हमारी पार्टी को राजनीतिक हिंसा करने वाली पार्टी बनाकर पेश कर सकें।

मतदान के बाद भी केरल के साथी इसकी उम्मीद लगाए थे कि हमें आधी से ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन, हमारी ज्यादातर सीटों पर एक लाख के करीब या उससे ज्यादा वोट से हार हुई। हम जनता के मूड को समझने में विफल रहे, जो गंभीर चिंता का विषय है। गलतियों तथा कमजोरियों को दुरुस्त करने के लिए राज्य कमेटी को समुचित कदम उठाने चाहिए।

हालांकि केरल में सीटें जीतने की भाजपा की कोशिशें नाकाम रहीं, अपने वोट का एक हिस्सा यूडीएफ को हस्तांतरित करने के बावजूद, एनडीए को 15.56 फीसद वोट मिल गया। यह गंभीर चिंता का विषय है। केरल में भाजपा के फैलाव को रोकने के लिए धीरज के साथ और सतत रूप से राजनीतिक, विचारधारात्मक तथा सांगठनिक अभियान चलाना होगा। पुन: अपने कुछ परंरागत आधारों में पार्टी की वोट हासिल होने की सामर्थ्य में गिरावट हुई है। पार्टी को गंभीरता से इसकी पड़ताल करनी चाहिए कि क्यों पार्टी की कड़ी मेहनत और राज्य में उसकी सरकार के अच्छे प्रदर्शन के

बावजूद, उसके आधार का विस्तार नहीं हो पा रहा है।

प0 बंगाल

17वीं लोकसभा के चुनाव में प0 बंगाल में पार्टी को बहुत गंभीर धक्का लगा है। इस बार का चुनाव परिणाम, पार्टी के इतिहास का सबसे बुरा चुनावी प्रदर्शन है। शुरूआती गणनाओं के अनुसार, इस चुनाव में सी पी आइ (एम) को 6.28 फीसद और वाम मोर्चा को 7.44 फीसद वोट मिले हैं। यह वाम मोर्चा के लिए, 2014 के 29.61 फीसद से, 22.17 फीसद की गिरावट को दिखाता है। 2016 के विधानसभाई चुनाव में वाम मोर्चा को 26.30 फीसद वोट मिले थे। उस चुनाव में वाम मोर्चा ने दो-तिहाई सीटें ही लड़ी थीं और एक तिहाई सीटें तालमेल के तहत कांग्रेस के लिए छोड़ दी थीं। अगर इन एक-तिहाई सीटों का वोट भी जोड़ दिया जाए तो वाम मोर्चा जमा कांग्रेस जमा वाम मोर्चा-समर्थित निर्दलीयों का सम्मिलित वोट 39.43 फीसद बैठता था। इस तरह, इस चुनाव में हमारे मत फीसद में भारी गिरावट आयी है।

2019 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 43.28 फीसद वोट मिला है, जबकि 2014 में उसे 39.35 फीसद वोट मिला था और 2016 में 45.01 फीसद। 2019 के चुनाव में भाजपा को 40.25 फीसद वोट मिला है, जबकि 2014 में उसे 16.84 फीसद वोट मिला था, जो 2016 में 10.16 फीसद रह गया था। जहां तृणमूल ने इस चुनाव में अपने मत फीसद में मामूली बढ़ोतरी की है, इसे मुख्यत: धांधली का और विपक्ष का वोट पड़ने से रोके जाने का नतीजा कहा जा सकता है। बहरहाल, भाजपा ने अपने मत फीसद में 23 फीसद से ज्यादा की बहुत भारी बढ़ोतरी दर्ज करायी है।

पिछले आठ साल के दौरान सी पी आइ (एम) को तृणमूल कांग्रेस के हाथों भीषण फासीवादी हमले का सामना करना पड़ा है। इस दौरान जिन 214 वामपंथी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गयी हैं, उनमें 209 सी पी आइ (एम) के कार्यकर्ता ही थे। हजारों कार्यकर्ताओं को अपने घर-परिवारों से दूर, निर्वासन में रहना पड़ रहा है। दाब-धोंस और धमकियों का दौर-दौरा बढ़ता ही गया है। इन बहुत ही मुश्किल तथा प्रतिकूल हालात के बावजूद, लाखों पार्टी सदस्यों तथा कार्यकर्ताओं में इस चुनाव में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया था।

इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बहुत भारी शासकविरोधी भावना काम कर रही थी। भावना को इसका काफी फायदा मिला। सी पी आइ (एम) तथा वाम मोर्चा को ऐसी ताकत के रूप में नहीं देखा जा रहा था, जो तृणमूल कांग्रेस का विकल्प

दे सकती, जबकि केंद्र सरकार के समर्थन के बल पर और अपनी भारी प्रचार बमबारी के सहारे, भाजपा को ऐसे विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था।

2018 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में भारी हिंसा तथा धांधली हुई थी और जनतंत्र का पूरी तरह से मजाक बनाकर रख दिया गया था। बड़े पैमाने पर हिंसा तथा आतंक के जरिए, लोगों को नामजदगी के पर्चे दाखिल करने से ही रोकने से लेकर और चुनाव के बाद धांधली समेत, ऐसे-ऐसे हथकंडे आजमाए गए थे, जिनके बारे में इससे पहले किसी ने सुना तक नहीं था। तृणमूल कांग्रेस ने 40,000 से ज्यादा स्थान बिना चुनाव के ही जीत लिए थे। इस तरह का अभूतपूर्व आतंक, 2019 के संसदीय चुनावों को प्रभावित करने के लिए ही फैलाया गया था। लेकिन, इस अनुभव ने जनता के बीच तृणमूल विरोधी भावनाओं को और गहरा करने का ही काम किया। इन भावनाओं पर आतंक के जरिए ही अंकुश रखा जा रहा था।

पंचायत चुनावों के बाद के दौर में सी पी आइ (एम) तथा वामपंथ ने समूचे राज्य में अनेक सतत आंदोलन तथा संघर्ष चलाए थे। इनमें बड़ी संख्या में मेहनतकश जनता ने और खासतौर पर किसानों ने, मजदूर वर्ग ने और युवाओं ने हिस्सेदारी की थी। इसी सब का चरमोत्कर्ष 2019 की फरवरी की अभूतपूर्व ब्रिगेड रैली में देखने को मिला था। हालांकि, हमारे संघर्षों को जनता से अच्छा समर्थन मिल रहा था और उनमें जनता की हिस्सेदारी बढ़ती रही थी, फिर भी इसे चुनाव में लोगों के वोट में तब्दील नहीं किया जा सका। लोग आम तौर पर तृणमूल कांग्रेस को हराने को सबसे ऊपर रख रहे थे और इस पहलू से सी पी आइ (एम) और वाम मोर्चा को वहनीय विकल्प की तरह देखा ही नहीं जा रहा था।

पार्टी ने 2019 का चुनाव, 22वीं पार्टी कांग्रेस द्वारा अपनायी गयी राजनीतिक लाइन के आधार पर, केंद्रीय कमेटी द्वारा तय की गयी चुनावी लाइन के आधार पर लड़ा था। पार्टी ने आह्वान किया था: 'मोदी हटाओ, देश बचाओ और तृणमूल हटाओ, बंगाल बचाओ।' इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, केंद्रीय कमेटी ने तय किया था कि ऐसी चुनावी कार्यनीति आजमायी जानी चाहिए, जो तृणमूलविरोधी, भाजपाविरोधी वोट की एकता को अधिकतम करे।

इसी आधार पर, केंद्रीय कमेटी के अनुमोदन से पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी ने कांग्रेस पार्टी से यह प्रस्ताव किया था कि दोनों की सिटिंग सीटों पर आपस में कोई टक्कर नहीं होनी चाहिए। पुन:, पार्टी ने अपनी दो सिटिंग सीटों के अलावा 20 और प्राथमिकतावाली सीटों की पहचान की थी, जहां से पार्टी का लड़ना जरूरी था।

पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा के अन्य घटक दल परंपरागत रूप से 10 सीटों पर चुनाव लड़ते आए थे। शेष आठ सीटों के लिए तय किया गया था कि वहां तृणमूल तथा भाजपा, दोनों को हराने में समर्थ सबसे अच्छे उम्मीदवार की पहचान की जाएगी और उसे ही हम अपना समर्थन देंगे। लेकिन, अंतत: सी पी आइ (एम) ने 31 सीटों पर तथा वाम मोर्चा के अन्य घटकों ने 9 सीटों पर और इस तरह राज्य की कुल 42 में से 40 सीटों पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी ने अन्य दो सीटों पर जीत हासिल की है, जहां से वाम मोर्चा ने चुनाव नहीं लड़ा था। ये दोनों उसकी सिटिंग सीटें थीं।

कांग्रेस पार्टी ने आपस में न टकराने के हमारे प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया। इससे, जनता के बीच फैली इस धारणा को और भी बल मिला कि वाम मोर्चा, तृणमूल के खिलाफ वहनीय विकल्प नहीं बन पाएगा। 2016 में हुए विधानसभाई चुनाव के दौरान, भाजपा अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से इसका एलान किया था कि भाजपा की इन विधानसभाई चुनावों में दिलचस्पी नहीं है और वह लोकसभा चुनावों पर ही ध्यान केंद्रित करेगी। इसने एक माने में तृणमूल की सत्ता में वापसी को सुगम बनाया था और इस मौके का भाजपा ने बंगाल में जनता के बीच घुसपैठ करने में पूरा-पूरा फायदा उठाया। इसी दौर में इस राज्य में आरएसएस की शाखाएं तथा इकाइयां, बढ़कर कई गुनी हो ज्यादा हो गयीं। इस राज्य में भाजपा ने पिछले कई वर्षों से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वाला जो प्रचार अभियान छेड़ा हुआ था, उसे इस सब ने और तेज कर दिया। इस आक्रामक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की मुहिम के अनेक रूप सामने आए। भाजपा ने खुल्लमखुल्ला रामनवमी, हनुमान जयंती आदि के हमलावर तरीके से आयोजन किए, जिनमें सार्वजनिक जुलूसों में बच्चों को तलवारें तथा अन्य हथियार देकर उतारा गया। तृणमूल भी होड़ में उतर गयी और उसने भी रामनवमी, हनुमान जयंती तथा अन्य हिंदू त्योहारों पर समांतर आयोजन किए। यह सब, इस पहले से बन चुकी धारणा की पृष्ठभूमि में हो रहा था कि तृणमूल कांग्रेस ने तुष्टीकरण के विभिन्न कदमों के जरिए ही अल्पसंख्यक समुदाय को गोलबंद किया था। इस तरह सांप्रदायिक विभाजन और मजबूत हो गया और सघन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के हालात बन गए। 2016 के विधानसभाई चुनाव के बाद से इस राज्य में सांप्रदायिक टकराव की 47 वारदातें हुई थीं, जबकि वाम मोर्चा के शासन में तो प0 बंगाल में ऐसी घटनाओं का किसी ने नाम तक नहीं सुना था।

ये चुनाव बहुत ही ध्रुवीकृत वातावरण में लड़े गए थे, जहां भाजपा और तृणमूल कांग्रेस, दोनों ही इस तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से फायदा उठाने की कोशिश कर रही थीं।

पार्टी की राज्य कमेटी ने इस चुनाव के नतीजों की आरंभिक समीक्षा की है।

ये चुनाव प0 बंगाल में पार्टी को सबसे बुरा धक्का लगने को दिखाते हैं। आरंभिक समीक्षा में जिन राजनीतिक-सांगठनिक कमजोरियों की पहचान की गयी है, उनसे ईमानदारी से निपटा जाना चाहिए। मुख्यत: जनता का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए, अनेक महत्वपूर्ण सांगठनिक कदम उठाने होंगे। जनता के जिस हिस्से ने तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए भाजपा को वोट दिया है, उसकी इस तरह की समझ सांप्रदायिक ताकतों द्वारा पेश किए जाने वाले खतरे को बहुत-बहुत कम कर के आंकती है। यह समझ हमारी पार्टी की कांग्रेस की समझदारी और केंद्रीय कमेटी द्वारा तय की गयी चुनावी कार्यनीतिक लाइन के विपरीत है। राज्य कमेटी द्वारा की गयी आरंभिक समीक्षा दिखाती है कि हालांकि हालांकि, मतदान के इस तरह के पैटर्न में पार्टी के सदस्य तथा कार्यकर्ता तो शामिल नहीं हुए थे, फिर भी हमारे परंपरागत मतदाताओं के कुछ हिस्सों ने ऐसा किया हो सकता है। राज्य कमेटी को, इस तरह के रुझान को रोकने के लिए किए गए प्रयासों की गंभीरता से छानबीन करनी चाहिए। इसका आकलन करने के लिए भी जांच-परख की जरूरत है कि कहीं हमारे समर्थन आधार के भी कुछ हिस्से तो सांप्रदायिक ताकतों के असर में नहीं आ गए हैं। इस तबके को दोबारा पार्टी के दायरे में लाना होगा।

पार्टी की स्वतंत्र शक्ति को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। जनता की चिंता के मुद्दों पर जमीनी स्तर पर सतत गोलबंदी की योजना बनायी जानी चाहिए और उसे लागू किया जाना चाहिए। हमारे अभियानों का मुख्य जोर सांप्रदायिकता के बढ़ती आफत का विचारधारात्मक, राजनीतिक तथा सांगठनिक रूप से मुकाबला करने पर रहना चाहिए। बेशक, राज्य सरकार तथा सत्ताधारी पार्टी की जनविरोधी नीतियां तथा उसके द्वारा छेड़ा गया आतंक, हमारे अभियान का महत्वपूर्ण तत्व होंगे।

त्रिपुरा

त्रिपुरा में लोकसभा के चुनाव सी पी आइ (एम) और वाम मोर्चा के खिलाफ लगातार जारी आतंक तथा हिंसा की पृष्ठभूमि में हुए, जिसका सिलसिला 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो गया था।

सत्ताधारी भाजपा ने इस चुनाव में आतंक के हथकंडों, सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने की कोशिशों और विभिन्न सरकारी योजनाओं व लाभों

के जरिए मतदाताओं को लुभाने के योग का इस्तेमाल किया था।

राज्य के दो लोकसभाई क्षेत्रों के लिए चुनाव, दो अलग-अलग चरणों में हुआ था। पहले चरण में त्रिपुरा पश्चिमी लोकसभाई क्षेत्र में चुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा के हथियारबंद गिरोहों ने मुकम्मल धांधली की थी। कुछ इलाके छांटकर वहां मतदाताओं को अपने घर या इलाके से बाहर पांव ही नहीं रखने के लिए मजबूर कर दिया गया। वाम मोर्चा के मतदाताओं को मतदान केंद्रों से खदेड़ दिया गया। बड़े पैमाने पर मतदान एजेंटों को मतदान केंद्रों में घुसने ही नहीं दिया गया और मतदान केंद्रों पर कब्जा कर धांधली की गयी। कुल मतदान केंद्रों में से आधे से ज्यादा इन धांधलियों की चपेट में आए थे। यहां मतदान के बाद हमारी पार्टी ने 846 मतदान केंद्रों में पुनर्मतदान कराने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने भी पहले 400 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने की सोची थी, लेकिन अंतत: सिर्फ 168 मतदान केंद्रों पर ही पुनर्ममतदान के आदेश दिए गए। लेकिन, 12 मई को हुए इस पुनर्मतदान में भी बड़े पैमाने पर डराने-धमकाने तथा धांधली का सहारा लिया गया।

इसी के चलते पार्टी राज्य कमेटी ने अपनी समीक्षा में कहा था कि त्रिपुरा पश्चिमी लोकसभाई क्षेत्र के चुनाव नतीजों की समीक्षा करने का कोई अर्थ ही नहीं है।

त्रिपुरा पूर्वी लोकसभाई क्षेत्र का चुनाव, राज्य में पहले चरण के मतदान में हुई बड़े पैमाने पर धांधली को देखते हुए, 18 अप्रैल से स्थगित कर, 23 अप्रैल को कराया गया। याद रहे कि त्रिपुरा पूर्वी विधानसभाई क्षेत्र में भी, कुल 1,645 मतदान केंद्रों में से 27 फीसद यानी 443 मतदान केंद्रों में सी पी आइ (एम) पोलिंग एजेंट ही नहीं दे पायी थी और इनमें से ज्यादातर मतदान केंद्रों में भाजपा ने फर्जी वोट डलवाए थे। भाजपा ने यह सीट 4,82,126 वोट यानी कुल डाले गए वोट का 46.32 फीसद हासिल कर जीत ली। कांग्रेस, 2,77,836 यानी 26.69 फीसद वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही, जबकि सी पी आइ (एम) 2,00,963 यानी 19.31 फीसद वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही। आइपीएफटी को 45,304 यानी 4.35 फीसद वोट मिले।

इस लोकसभाई क्षेत्र में हमारे वोट में भारी गिरावट हुई है। जहां पिछले विधानसभाई चुनाव में हमें करीब 45 फीसद वोट मिले थे, इस बार हमें 19.31 फीसद वोट ही मिले हैं, जो 25.57 फीसद की गिरावट को दिखाता है।

सी पी आइ (एम) तथा वाम मोर्चा के मतदाताओं के खिलाफ जोर-जबर्दस्ती और दाब-धोंस के हथकंडे आजमाने के अलावा भाजपा ने बेशुमार पैसे की ताकत का तथा ज्यादातर इलैक्ट्रोनिक मीडिया व पत्र-पत्रिकाओं का अपने पक्ष में इस्तेमाल किया

था। उसने बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था। भाजपा ने नागरिकता संशोधन विधेयक की जोर-शोर से वकालत की थी। चूंकि इस राज्य में रहने वाले गैर-आदिवासियों में अनेक के नाते-रिश्तेदार अब भी बांग्लादेश में रहते हैं, इस विधेयक के प्रावधानों के चलते गैर-आदिवासियों के एक हिस्से ने भाजपा का समर्थन किया।

विधानसभा चुनाव की तुलना में इस चुनाव में कांग्रेस के वोट में बढ़ोतरी के निम्नलिखित कारण थे। हमारे चुनाव प्रचार का मुख्य जोर भाजपा को हराने और उसे हटाकर केंद्र में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनवाने पर था। जो लोग भाजपा को केंद्र में सत्ता से हटाने के पक्ष में थे, वे इसके लिए कांग्रेस को ज्यादा व्यावहारिक विकल्प की तरह देखते थे। इस तरह की सोच मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बड़े हिस्से के बीच थी और इसमें वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे पक्ष में वोट डाला था।

कांग्रेस के चुनाव अभियान में आदिवासी पहचान पर और नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध पर जोर रखा गया था। कांग्रेस की उम्मीदवार, अंतिम आदिवासी राजा की पोती है और इसने आदिवासी राज परिवार के पक्ष में भावनाएं जगायीं। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे आदिवासी मतदाताओं और आइपीएफटी समर्थकों के भी एक हिस्से ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल दिया। भाजपा अपने आतंक अभियान में मुख्यत: सी पी आइ (एम) को ही निशाना बनाए रही है और इससे कांग्रेस को ऐसे हमलों से बख्शे रखा है।

इस चुनाव में हमारी पार्टी के खराब प्रदर्शन की मुख्य वजह यह थी कि राज्य में असामान्य हालात बने होने के चलते हम एक असरदार चुनाव अभियान चलाने में और जनता तक पहुंच पाने में असमर्थ रहे। पिछले 14 महीनों से 50-60 लोकल कमेटियां और बहुसंख्या में पार्टी ब्रांचें, काम नहीं कर पा रही हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि आतंक राज कायम होने के चलते, पार्टी सदस्यों की बड़ी संख्या निष्क्रिय ही बनी रही।

फिर भी, अपने परंपरागत इलाकों में आदिवासी जनता के बीच हमारे समर्थन में भी अच्छी-खासी गिरावट आयी है। लोगों के बीच हमारे समर्थन आधार पर यह गिरावट, इससे पहले स्वायत्त जिला परिषद के अंतर्गत ग्राम कमेटियों के चुनावों में भी देखने में आयी थी। आदिवासी युवाओं तथा मध्य वर्ग के बीच, आदिवासी पहचान का और आदिवासी संकीर्णतावादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ा है। इन तबकों के बीच

हमारे विचारधारात्मक काम की कमजोरी स्वत:स्पष्ट है।

इस राज्य में चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। वोटों की गिनती के बाद, सत्ताधारी पार्टी ने भयंकर हमले छेड़ दिये। इन हमलों की शुरूआत मतगणना केंद्रों में ही हमारे मतगणना एजेंटों पर हमलों से हो गयी थी और विभिन्न जगहों पर ये हमले बाद में भी जारी रहे हैं। हमारी पार्टी के तथा जनसंगठनों के कार्यालयों पर हमले किए गए हैं, घरों व दूकानों पर हमले किए गए हैं, मतदान एजेंटों पर तथा प्रमुख कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए हैं।

पार्टी संगठन, सदस्यों व समर्थकों की हिफाजत करना और जनता के साथ फिर से जीवंत रिश्ते कायम करना, चुनाव के बाद के दौर के हमारे मुख्य कामों में हैं।

अन्य राज्य

तमिलनाडु में द्रमुक के नेतृत्ववाले गठबंधन का हिस्सा होने के नाते हमने, जो दो सीटें लड़ी थीं, दोनों जीत ली हैं। दूसरे राज्यों में प्रदर्शन बहुत ही असंतोषजनक रहा है और हमारे मत फीसद में गिरावट हुई है। एक महाराष्ट्र की डिंडोरी सीट ही है, जहां हमें पिछले चुनाव से ज्यादा वोट मिला है और हमने एक लाख की रेखा पार कर ली है। यहां ग्रामीण आदिवासी तबकों को गोलबंद करने में किसान लॉन्ग मार्च ने मदद की थी। हमने जिन 71 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उन सभी के नतीजे का ब्यौरा तालिका-2 में दिया जा रहा है।

तमिलनाडु: सी पी आइ (एम) ने तमिलनाडु में द्रमुक के साथ चुनावी तालमेल किया और इस राज्य में द्रमुक के नेतृत्ववाले गठबंधन का हिस्सा बन गयी। इस तालमेल के आधार पर सी पी आइ (एम) ने दो सीटों पर चुनाव लड़ा था—मदुरे और कोयम्बटूर। सी पी आइ (एम) ने ये दोनों सीटें जीत लीं।

कोयम्बटूर में हमारी पार्टी ने 5,71,150 वोट हासिल किए, जो कुल वैध वोटों का 45.66 फीसद होता है। मदुरै में पार्टी को 4,47,075 वोट मिले यानी कुल वोट का 44 फीसद हिस्सा। राज्य में पड़े कुल वोट में हमारा हिस्सा 2.40 फीसद रहा।

महाराष्ट्र में हमने डिंडोरी सीट पर अपने ही बल पर चुनाव लड़ा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ सीटों की साझेदारी पर बातचीत विफल हो गयी क्योंकि वह डिंडोरी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। पालघर की सीट पर भी हमने विचार किया था। इस सीट पर एक मजबूत स्वतंत्र उम्मीदवार खड़ा हुआ जिसे हमने, चंद महीनों में ही होने जा रहे चुनावों में विधानभाई सीटों पर उनके समर्थन के बदले में, इस

चुनाव में अपना समर्थन दे दिया।

इस चुनाव में डिंडोरी में हमें 1,09,570 वोट मिले, जबकि 2014 में 72,599 वोट मिले थे। हमारा मत फीसद, 2014 के 7.48 फीसद से बढ़कर इस बार 9.63 फीसद हो गया। हम तीसरे स्थान पर रहे।

राजस्थान में, जहां पिछले विधानसभाई चुनाव में हमारे वोट में बढ़ोतरी हुई थी और हमने दो विधानसभाई सीटें जीती थीं, हमने तीन लोकसभाई सीटों पर चुनाव लड़ा था। सीकर में हमें 31,462 (2.37 फीसद) वोट मिले जबकि 2014 में 53,134 (4.98 फीसद) वोट मिले थे। चुरू में हमें 25,090 (1.89 फीसद) वोट मिले। विधानसभाई चुनाव में इसी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत भादरा विधानसभाई सीट पर हमें 81,655 वोट मिले थे और हमने यह सीट जीती थी। लेकिन, इस लोकसभाई चुनाव में आठों विधानसभाई क्षेत्रों को मिलाकर उक्त वोट आया है। बीकानेर में हमें 8,997 (0.82 फीसद) वोट मिले हैं। इसी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली श्री डूंगरगढ़ विधानसभाई सीट हमने 73,376 वोट हासिल कर जीती थी। साफ है कि विधानसभाई तथा लोकसभाई चुनाव में मतदान के पैटर्न में भारी अंतर है। इन्हीं हालात में पार्टी केंद्र ने राजस्थान राज्य कमेटी को सलाह दी थी कि उन संसदीय सीटों पर लड़ने के संबंध में पुनर्विचार करे, जिनके अंतर्गत हमारी जीती विधानसभा सीटें पड़ती हैं। लेकिन, राज्य कमेटी ने लड़ने का आग्रह किया।

आंध्र प्रदेश में हमने फिल्म अभिनेता पवन कल्याण की जन सेना पार्टी के साथ गठबंधन कर, दो सीटों पर चुनाव लड़ा था। दोनों सीटों पर हमें बहुत कम वोट मिले। नेल्लोर में हमें 18,830 (1.46 फीसद) वोट मिले और हम तीसरे स्थान पर रहे। कुर्नूल में हमें 18,919 (1.6 फीसद) वोट मिले और हम पांचवे स्थान पर रहे। कुल मिलाकर इस राज्य में हमारा मत फीसद 0.12 रहा।

तेलंगाना में हमने सी पी आइ के साथ तालमेल कर दो सीटों पर चुनाव लड़ा था। खम्मम में हमें 57,102 (5.01 फीसद) वोट मिले और हम तीसरे स्थान पर रहे। नलगोंडा में हमें 25,089 (2.13 फीसद) वोट मिले और हम चौथे स्थान पर रहे। राज्य में हमारा कुल मत प्रतिशत रहा, 0.44।

असम में हमने दो सीटों पर चुनाव लड़ा—कोकराझार और लखीमपुर। कोकराझार में हमें 28,128 (1.9 फीसद) वोट मिले और हम पांचवे स्थान पर रहे। लखीमपुर में सी पी आइ भी मैदान में उतर पड़ी और उसे 13,378 वोट मिले। यहां हमें 12,809 (1 फीसद) वोट ही मिले और हम पांचवे स्थान पर रहे।

बिहार में राजद के साथ तालमेल की हमारी कोशिशें कामयाब नहीं हुईं। यहां हमने एक ही सीट पर चुनाव लड़ा, समस्तीपुर जिले के अंतर्गत, उजियारपुर। इस सीट पर हमारा मत फीसद घटकर करीब आधा रह गया। इस चुनाव में हमें 27,577 (2.85 फीसद) वोट मिले, जबकि 2014 में 53,044 (6.18 फीसद) वोट मिले थे।

हिमाचल प्रदेश में मंडी में हमें 14,838 (1.58 फीसद) वोट मिले। यह 2014 के 13,965 (1.92 फीसद) वोट से संख्या में मामूली बढ़ोतरी दिखाता है। लेकिन, फीसद के लिहाज से हमारा वोट घटा है।

हरियाणा में हमने जिस एक सीट पर चुनाव लड़ा था, उस पर हमे 9,150 वोट मिले जबकि 2014 में 6,533 वोट ही मिले थे। हमारा मत फीसद 0.56 से बढ़कर 0.78 फीसद हो गया है।

कर्नाटक में चिक्कबल्लापुर से चुनाव लड़ा, जहां हमारा वोट 2014 के 26,000 से घटकर 18,000 रह गया और मत फीसद, 2.06 से घटकर 1.34 हो गया।

मध्य प्रदेश में हमने रींवा से चुनाव लड़कर 10,453 (1.03 फीसद) वोट हासिल किए।

ओडिशा में हमने भुवनेश्वर संसदीय सीट लड़ी और 23,026 (2.29 फीसद) वोट प्राप्त किए। शुरू में राज्य कमेटी के साथ यह सहमति बनी थी कि सुंदरगढ़ के लोकसभा सीट के अपने उम्मीदवार के लिए हमारे समर्थन के बदले में, कांग्रेस इस सीट से हमें समर्थन देगी। बहरहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह समझदारी मतदान तक जा पायी।

झारखंड में हमने राजमहल की सीट लड़कर, 35,586 वोट हासिल किए, जो 2014 के 58,034 वोट से गिरावट को दिखाता है। हमारा मत फीसद, 6.1 से घटकर 3.4 पर आ गया।

उत्तराखंड में हमने टेहरी-गढ़वाल की सीट पर चुनाव लड़ा। हमारे वोट की संख्या में तो मामूली बढ़ोतरी हुई, लेकिन मत फीसद 0.85 से घटकर 0.76 हो गया।

उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ तथा अंडमान-निकोबार से इस बार हमने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, जबकि 2014 में वहां हमने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे।

राज्य विधानसभाओं के चुनाव

ओडिशा, आंध्र प्रदेश के विधानसभाई चुनावों में और पश्चिम बंगाल के उपचुनावों में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा है।

इस रुझान का एकमात्र अपवाद है, ओडिशा का विधानसभाई चुनाव परिणाम। यहां हम अपनी सिटिंग बोनाई सीट 59,939 (34.67 फीसद) वोट हासिल कर बचाने में कामयाब रहे हैं। 2014 में हमें यहां 39,125 वोट मिले थे। हमारी मत शक्ति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

शुरू में यह समझदारी थी कि कांग्रेस, जिस लोकसभाई सीट के अंतर्गत बोनाई सीट आती है, उस पर अपने उम्मीदवार के समर्थन के बदले में, इस विधानसभाई सीट पर हमें समर्थन देगी। लेकिन, इस समझदारी को नकारते हुए, विधानसभाई सीट पर एक बागी कांग्रेसी उम्मीदवार खड़ा हो गया। (विवरण, तालिका-3 में)

हमारी स्वतंत्र शक्ति में गिरावट जारी है

ये नतीजे, जो इससे पहले के दो चुनावों में लगे धक्कों के ऊपर से आए हैं, बहुत ही स्पष्ट रूप से इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि हमारी स्वतंत्र शक्ति और राजनीतिक हस्तक्षेप की क्षमताओं में बहुत भारी गिरावट हुई है। हमने जो सीटें लड़ी थीं, उन पर कुल मिलाकर मत फीसद और गिरावट हुई है। तमिलनाडु को और एक सीमित तरीके से आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना को छोड़कर, दूसरे किसी भी राज्य में हमारा क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कोई गठबंधन या तालमेल नहीं हुआ है।

हमारे मजबूत राज्यों में हमारे मत फीसद में गिरावट बहुत भारी चिंता का विषय है। राज्य कमेटियों द्वारा की गयी आरंभिक समीक्षाएं हम पीछे दर्ज कर आए हैं। फिर भी इनमें से किसी में भी इसका आकलन नहीं है कि हमारे बुनियादी वर्गों—मजदूर वर्ग, किसानों तथा खेत मजदूरों—ने किस तरह से वोट डाले। हमसे जनता के अलगाव और हमारे परंपरागत मतदाताओं के कुछ हिस्सों के हमारा साथ छोड़ जाने, दोनों को समझने के लिए कहीं गहरी समीक्षा की जरूरत है। कुछ खास कमजोरियां हैं जिन्हें हमें सिर्फ दर्ज ही नहीं करना चाहिए बल्कि दुरुस्त भी करना चाहिए।

1) पिछले कुछ वर्षों के दौरान पार्टी के वर्गीय व जनसंगठन, जन आंदोलन तथा संघर्ष छेड़ने में लगे रहे हैं। बहरहाल, देश के स्तर पर यह काम असमान रहा तथा सतत तरीके से नहीं चलाया जा सका है। मजदूर वर्ग ने दो दिन की संयुक्त औद्योगिक हड़ताल की थी, जिसमें देश के करीब छः करोड़ मजदूरों के हिस्सा लिया था। कृषि संकट के मुद्दे पर किसान मोर्चे ने बड़े-बड़े आंदोलन किए थे। महाराष्ट्र का लॉन्ग मार्च, राजस्थान में किसानों के संघर्ष और चरमोत्कर्ष के रूप में दिल्ली में विशाल मजदूर-किसान-खेत मजदूर रैली।

इस दौर में हमारे मजबूत राज्यों में भी बड़ी-बड़ी जन गोलबंदियां हुई हैं। केरल में 56 लाख महिलाओं ने ऐतिहासिक महिला प्राचीर बनायी थी। प0 बंगाल में वाम मोर्चा ने ब्रिगेड परेड मैदान में अभूतपूर्व विराट रैली की थी। इससे पहले, राज्य भर को बांधते हुए, अनेकानेक जन-कार्रवाइयां आयोजित की गयी थीं। इन सभी में पहले की तुलना में ज्यादा संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था। त्रिपुरा में बहुत ही प्रतिकूल हालात के बावजूद, पार्टी के लिए कुछ राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना संभव हुआ था।

साफ है कि इन जन संघर्षों में लोगों की गोलबंदी को, सी पी आइ (एम)/ वामपंथ के लिए वोटों में तब्दील नहीं किया जा सका है। हमारे संघर्षों में शामिल होने वाले लोगों को राजनीतिक बनाने में जो कमजोरी बनी हुई है, उससे फौरन उबरे जाने की जरूरत है। ऐसा करने में असमर्थता, हमारे द्वारा छेड़े गए संघर्षों में भागीदारी और चुनाव के समय मतदान के बीच की खाई को और चौड़ा करेगी।

2) युवाओं के बीच हमारे प्रति आकर्षण सीमित बना हुआ है। हम एक के बाद एक पार्टी कांग्रेसों में इसे दर्ज करते आए हैं और इस समस्या से निपटने तथा इस स्थिति से उबरने के कदमों के बारे में फैसले करते आए हैं। साफ है कि इन कदमों को या तो लागू ही नहीं किया गया है या वे सफल नहीं हुए हैं। नवउदारवाद अपने आप में ऐसी परिस्थितियां थोपता है, जो युवाओं के गैर-राजनीतिककरण की ओर ले जाती हैं। शिक्षा के निजीकरण का नतीजा यह हुआ है कि निजी शिक्षा संस्थाओं में राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लग गया है। देश भर में सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों तथा स्कूलों में, अपने छात्र संघ के चुनाव के छात्रों के जनतांत्रिक अधिकार को गंभीर रूप से सीमित कर दिया गया है। ट्यूटोरियल कॉलेजों की बेतहाशा बढ़ोतरी ने, जहां राजनीतिक गतिविधियों पर रोक ही है, करोड़ों युवाओं का किसी भी तरह की राजनीतिक चेतना से दूर ही रखा जाना सुनिश्चित किया है। बेरोजगारी के रिकार्ड ऊंचाई पर होने के बावजूद, हम जुझारू कार्रवाइयों में युवाओं को नहीं खींच पाए हैं।

इन परिस्थितियों में युवाओं तक पहुंचने का एक प्रमुख तरीका, सोशल मीडिया तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के संचार उपकरणों तक उन तक पहुंच बनाना ही है। भाजपा ने, युवाओं के बीच अपने संदेशों का प्रसारण करने और उन्हें प्रभावित करने के लिए, इन उपकरणों का सफलता के साथ इस्तेमाल किया है। हमारी पार्टी को फौरन इस प्रश्न से दो-चार होना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर भी तथा राज्यों के स्तर पर भी, आवश्यक उपाय करने चाहिए।

3) शहरी इलाकों में, शहरी गरीबों और मध्य वर्ग के बीच, हमारे प्रति आकर्षण घट रहा है। इस स्थिति को सुधारने के लिए हमने कुछ निर्णय लिए भी थे। लेकिन, उनसे कोई नतीजे हासिल नहीं हुए हैं।

4) अनेक चुनाव क्षेत्रों में हमें मिले कुल वोटों की संख्या, हमारे वर्गीय व जनसंगठनों की कुल सदस्यता से कम है। अगर कुछ लोगों की एक से अधिक संगठनों की सदस्यता में गिनती को भी हिसाब में ले लिया जाए, तब भी यह अंतर हमें एक बार फिर यही बताता है कि हमारे अपने जनसंगठनों के सदस्यों के राजनीतिककरण की प्रक्रिया, पर्याप्त से बहुत थोड़ी है।

सीखने वाले सबक

पार्टी को इस चुनावी प्रदर्शन से यह अप्रिय सबक लेना ही होगा कि पार्टी के स्वतंत्र जनाधार में गिरावट, जिसे हाल ही में एक के बाद एक कई पार्टी कांग्रेसों ने दर्ज भी किया था, और भी गहरी हो गयी है। ये खराब चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि पार्टी अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने में, अपनी सांगठनिक ताकत व काम-काज को बढ़ाने में और अपनी राजनीतिक हस्तक्षेप की सामर्थ्य को बढ़ाने में विफल रही है। पोलिट ब्यूरो तथा केंद्रीय कमेटी को, इस विफलता की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए।

(1) 2015 के दिसंबर में हुए कोलकाला प्लेनम ने, हमारे संगठन को चुस्त-दुरुस्त करने तथा मजबूत करने के लिए एक प्रस्ताव तथा रिपोर्ट को स्वीकार किया था, ताकि पार्टी एक जन लाइन को अपना सके। साफ है कि इनमें से अनेक निर्णयों को अमल में नहीं उतारा जा सका है।

प्लेनम के निर्णयों पर अमल की मुकम्मल समीक्षा करनी होगी। केंद्रीय कमेटी ने, 22वीं पार्टी कांग्रेस के निर्णय के अनुसार, अपनी 2018 जून की बैठक में तय किया था कि राज्य कमेटियों तथा उनकी विस्तारित बैठकों द्वारा एक साल की अवधि के लिए अपने जो काम तय किए गए थे, उन पर अमल की सभी राज्य कमेटियों द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। यह काम छः महीने के अंदर-अंदर यानी 2018 के अक्टूबर तक करना था।

बहरहाल, ज्यादातर राज्य कमेटियों ने, अपनी रिपोर्टों में तय किए गए प्लेनम के परिपालन के कामों पर अमल की समीक्षा नहीं की है।

यह समीक्षा हर हाल में अगले तीन महीने में यानी 2019 के अगस्त के आखिर

तक कर ली जानी चाहिए।

सांगठनिक उप-समिति को इन रिपोर्टों का अध्ययन करना होगा और आगे के लिए कार्रवाई का कार्यक्रम तय करना होगा, जिसे केंद्रीय कमेटी के सामने पेश किया जाएगा।

(2) एक के बाद एक, अनेक प्रस्तावों में जनसंगठनों के स्वतंत्र तथा जनतांत्रिक रूप से काम करने की जरूरत के रेखांकित किए जाने के बावजूद, अमल में इसे लागू नहीं किया गया है। इन वर्गीय व जनसंगठनों के इंचार्ज, पोलिट ब्यूरो सदस्यों को, अखिल भारतीय फ्रैक्शनों के साथ परामर्श कर के, संबंधित कारकूनों द्वारा ठोस जिम्मेदारियों का निर्वहन किए जाने और संबंधित जन संगठनों के सामने उपस्थित एजेंडा की प्राथमिकताओं, दोनों के संबंध में समयबद्ध परिपालन के लिए ठोस कदम सुझाने चाहिए।

(3) सभी राज्यों में तथा राष्ट्रीय स्तर पर, सोशल मीडिया समेत सभी उपलब्ध प्रौद्योगिकीय औजारों व उपकरणों का उपयोग करने के लिए, व्यापक आधार पर प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि पार्टी के सभी स्तरों पर इलैक्ट्रोनिक संचार के ताने-बाने को मजबूत किया जा सके।

(4) पार्टी तथा जनसंगठन, दोनों के ही स्तर पर, जनता के सामने खड़े ज्वलंत मुद्दों को लेकर, स्वतंत्र रूप से भी तथा समान विचारों वाली पार्टियों व सामाजिक ताकतों के साथ मिलकर भी, जनसंघर्ष छेड़ने के लिए योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।

(5) शहरी इलाकों में काम से संबंधित कमेटी को पार्टी के हस्तक्षेप के लिए एक एजेंडा सूत्रबद्ध करना चाहिए ताकि शहरी गरीबों तथा मध्य वर्ग के लगातार बढ़ते तबकों को गोलबंद किया जा सके।

नयी चुनौतियां

इन चुनावों में भाजपा की ऐसी निर्णायक जीत के बाद, निम्नलिखित फौरी चुनौतियों का सामने आना तय है, जिन का सामना करने के लिए देश तथा जनता को खुद को तैयार कर लेना चाहिए।

अ) अंतर्राष्ट्रीय पूंजी तथा घरेलू कार्पोरेटों का समर्थनप्राप्त इस नयी भाजपा सरकार का, नवउदारवादी आर्थिक सुधारों के जरिए जनता का शोषण और तेज करना तय है। पहले ही इसके संकेत आ चुके हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र का बड़े पैमाने पर

निजीकरण किया जाएगा, श्रम कानूनों में बदलाव किए जाएंगे, किसानों से खेती की जमीनों के हथियाए जाने को वैधता मुहैया कराने के लिए भूमि बैंकों का गठन किया जाएगा, आदि, इत्यादि। हमारी मेहनतकश जनता के विशाल बहुमत पर आर्थिक हमलों का बढ़ जाना तय है। इस सब के खिलाफ जनता के अधिकतम हिस्सों को गोलबंद करने में और इन मुद्दों पर संघर्ष छेड़ने में, पार्टी को अगुआई करनी चाहिए।

ब) इस चुनाव में हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो सुदृढ़ीकरण हुआ है उसे देखते हुए, सांप्रदायिक ताकतों के हमले का और तेज होना तय है। पार्टी को धार्मिक व भाषायी अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की हिफाजत का, उनकी सुरक्षा चिंताओं की तथा रोजी-रोटी के हालात में सुधार के मुद्दों का झंडाबरदार बनना चाहिए। भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र की हिफाजत करना तथा उसको मजबूत करना, हमारे अभियानों का स्थायी तत्व होना चाहिए।

स) संवैधानिक सत्ताओं को, संविधान के अंतर्गत आने वाली स्वतंत्र संस्थाओं को तथा संविधान के अंतर्गत नियमनकारी तंत्रों को कमजोर किए जाने की प्रक्रिया का आगे और तेज होना तय है। यह आरएसएस के लिए जरूरी है, जिसके द्वारा इन संस्थाओं के हथियाए जाने को और मजबूत किया जाएगा ताकि हमारे धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक, संवैधानिक गणराज्य को, 'हिंदू राष्ट्र' की उनकी विचारधारात्मक परियोजना में रूपांतरित किया जा सके। संविधान के अंतर्गत विभिन्न प्राधिकारों की हिफाजत करना तथा उन्हें मजबूत करना, हमारे अभियानों की एक स्थायी विशेषता होना चाहिए।

द) जनता के जनतांत्रिक अधिकारों तथा नागरिक स्वाधीनताओं पर हमलों का बढ़ना तय है। इन चुनावों में आरएसएस-भाजपा द्वारा संचालित अभियान के बाद, अब भारत में एक सुरक्षा राज्य गढ़ने की कोशिशें, व्यक्तियों के अधिकारों का और असहमति के उनके बुनियादी अधिकार का, बढ़ते पैमाने पर अतिक्रमण करने जा रही हैं। भाजपा नेताओं ने पहले ही इसके अनिष्टकरण संकेत देना शुरू कर दिया है।

नवउदारवादी सुधारों के और तेज होने के साथ, मजदूर वर्ग तथा मेहतनतकश जनता के अन्य तबकों, खासतौर पर किसानों तथा ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों पर, मुसलसल हमला होने जा रहा है।

निजी सेनाओं की गतिविधियां किसी न किसी बहाने से और तेज की जाएंगी और इस तरह लोगों को उनके जनतांत्रिक अधिकारों से वंचित किया जाएगा। कानून के जरिए परेशान करने के सहारे, जो चुन-चुनकर उत्पीड़ित किए जाने तक जाता है,

असहमति की आवाजों को कुचलने की कोशिश की जाएगी। पार्टी को इस चुनौती का सामने से मुकाबला करना चाहिए तथा उसे शिकस्त देनी चाहिए। इसके लिए उसे हमारी जनता के, जनतांत्रिक अधिकारों तथा नागरिक स्वाधीनताओं से प्यार करने वाले विशालतम हिस्सों को गोलबंद करना होगा।

काम

ऊपर दर्ज की गयी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि पार्टी:

1) मजदूर वर्ग, किसानों तथा खेत मजदूरों के ज्वलंत मुद्दों पर उनके विस्तृत तथा सघन संघर्ष छेड़े। मजदूर-किसान-खेत मजदूर संयुक्त कार्रवाइयों के लिए निकट अतीत में जो प्रयास किए गए थे, उन्हें और मजबूत किया जाना चाहिए और कार्रवाई के ठोस कार्यक्रम तय किए जाने चाहिए।

2) जन गतिविधियों को तेज करने के जरिए, स्थानीय मुद्दों पर संघर्ष छेड़ने के जरिए, पार्टी जबर्दस्त तरीके से जनता के बीच जाए और एक 'जन लाइन वाली क्रांतिकारी पार्टी' के प्लेनम के लक्ष्य को हासिल करे। जनता के बीच जाने में, पार्टी नेताओं को पहल करनी चाहिए।

3) जिन युवाओं ने हमारे चुनाव अभियान में हिस्सा लिया है, उनके बड़े हिस्सों को जनसंगठनों में खींचा जाना चाहिए। इन नये हल्कों तथा उनके बीच से कार्यकर्ताओं को, पार्टी में भर्ती किया जाना चाहिए।

4) वामपंथी ताकतों की एकता को मजबूत किया जाना चाहिए और इसके लिए संबंधित वामपंथी पार्टियों के साथ वार्ताएं की जानी चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच और घनिष्ठ तालमेल होना चाहिए।

5) हमारे विचारधारात्मक अभियानों को मजबूत किया जाना चाहिए। सांप्रदायिकता का विचारधारात्मक रूप से मुकाबला करने पर खास ध्यान रहना चाहिए। सांप्रदायिक ताकतें जिस तरह पुराणपंथीपन, अंधविश्वासों आदि के प्रसार को बढ़ावा देने में लगी हुई हैं उसे देखते हुए, वैज्ञानिक मिजाज़ के प्रसार को इस अभियान का एक जरूरी हिस्सा होना चाहिए।

6) ऊपर दर्ज की गयी चुनौतियों का सामना करने के लिए, मुद्दा-आधारित अभियानों के लिए व्यापकतम-संभव तबकों को गोलबंद करने के लिए पार्टी को पहल करनी चाहिए।

7) अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा तथा उनकी सुरक्षा प्रश्न; दलितों पर अत्याचारों तथा उनके अधिकारों की रक्षा के प्रश्न; लैंगिक प्रश्न व महिलाओं के साथ सामाजिक उत्पीड़न के प्रश्न; और देश में आदिवासी समुदायों के प्रश्न; सभी पर संघर्ष मजबूत किया जाना चाहिए। हमने जो व्यापक मंच गठित किए हैं उन्हें, इन गतिविधियों में समान विचारवाले संगठनों से सक्रिय रूप से राब्ता कायम करना चहिए।

8) पार्टी के रोजमर्रा के काम-काज में फौरन आधुनिक संचार पद्धतियों व उपकरणों के उपयोग को जोड़ा जाना चाहिए।

9) पार्टी को फौरन ऊपर बताए गए सबकों को हाथ में लेना चाहिए और अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहिए ताकि पार्टी की स्वतंत्र सांगठनिक व राजनीतिक हस्तक्षेप की क्षमताओं को मजबूत किया जा सके।

10) नयी शिक्षा नीति के खिलाफ संघर्ष के लिए पार्टी को छात्र संगठन के साथ बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों आदि का एक व्यापक मोर्चा निर्मित करना चाहिए।

11) बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर पार्टी को ठोस रूप से लक्षित कार्यक्रम संगठित करने चाहिए।

12) त्रिपुरा में भाजपा और प0 बंगाल में तृणमूल व भाजपा की चुनौतियों और उनके द्वारा किए जा रहे हमलों का मुकाबला करने के लिए, बंगाल व त्रिपुरा में हमारी पार्टी में जोश भरना होगा। इस चुनाव के बाद, केरल की एलडीएफ सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें और तेज हो जाएंगी। पार्टी को, संघवाद के सिद्धांतों की हिमायत में अभियानों को मजबूत करना होगा और इस राज्य सरकार के साथ एकजुट होना होगा।

निष्कर्ष

इन चुनावों ने हमारे देश में राजनीतिक दक्षिणपंथ के हमले को सुदृढ़ किया है। राजनीतिक वामपंथ ही है जो दक्षिणपंथ के सुदृढ़ीकरण का प्रभावी तरीके से प्रतिरोध कर सकता है। सी पी आइ (एम) और वामपंथ, दक्षिणपंथी हमले की काट करने वाली अविचल विचारधारात्मक, राजनीतिक तथा सांगठनिक शक्ति हैं। अतीत में इस काम को सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में अंजाम दिया गया है। आज की कठिन परिस्थितियों में भी इस संघर्ष को आगे ले जाया जाएगा। न हत मनोबल होकर और न पराजितभाव के साथ बल्कि दोगुने जोश तथा संकल्प के साथ, सी पी आइ (एम),

अपनी कमजोरियों पर काबू पाने के लिए तथा खुद को व वामपंथ को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाएगी।

कम्युनिस्ट होने के नाते हम बुनियादी राजनीतिक/ सामाजिक बदलावों के जरिए, एक शोषणमुक्त समाज की स्थापना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समर्पित हैं। हम फिर जनता के बीच जाएंगे, उससे सीखेंगे और उसके साथ जीवंत रिश्ते कायम करेंगे तथा उसकी चिंताओं का झंडा बुलंद करेंगे। जो लोग हम से दूर हो गए हैं, उन्हें हम दोबारा अपने साथ लाएंगे।

हमारी पार्टी, भाजपा–आरएसएस की विचारधारा तथा राजनीति के खिलाफ लड़ाइयों को मुसलसल आगे ले जाएगी। जनता की आजीविकाओं को तबाह कर रही नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ पार्टी एक एकजुट प्रतिरोध खड़ा करेगी। इन संघर्षों को, जनतंत्र तथा जनता के जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षों के साथ–साथ, तेज किया जाएगा। वामपंथी तथा जनतांत्रिक ताकतों को खड़ा करने तथा आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाएगी।

टेबिल 1
सीपीआई(एम) का प्रदर्शन - सीटें लड़ी, जीतीं और वोटों का प्रतिशत

	1967	1971	1977	1980	1984	1989	1991	1996	1998	1999	2004	2009	2014	2019
अखिल भारतीय	19(62)	25(85)	22(53)	36(63)	22(59)	33(64)	35(60)	32(75)	32(71)	33(72)	43(69)	16(82)	9+2* (93+5*)	3 (69+2*)
	4.4%	5.1%	4.3%	6.1%	5.9%	6.6%	6.2%	6.1%	5.2%	5.4%	5.7%	5.3%	3.2% (3.5%*)	
आंध्र प्रदेश	0(9)	1(5)	0(6)	0(5)	1(2)	0(2)	1(2)	1(3)	0(3)	0(7)	1(1)	0 (2)	0(4)	0 (2)
	6.2%	2.8%	4.7%	3.6%	1.8%	2.4%	2.4%	2.9%	2.9%	1.4%	1.0%	1.3%	0.3%	0.12%
असम	—	0(2)	0(1)	0(1)		—	1(2)	1(2)	0(2)	0(2)	0(2)	0 (3)	0(3)	0 (2)
		1.4%	2.9%	9.2%			4.7%	3.9%	3.3%	1.8%	0.7%	0.7%	0.4%	0.12%
बिहार	0(2)	0(4)	0(2)	0(3)	0(3)	1(3)	1(1)	0(3)	0(4)	1(2)	0(1)	0 (5)	0(4)	0 (1)
	0.3%	0.8%	0.2%	0.9%	1.1%	1.4%	1.4%	0.8%	0.4%	1.0%	0.8%	0.5%	0.3%	0.07%
गुजरात	——	——	—	—	0(1)	—	—	0(1)			0(1)	0 (2)	0(1)	--
					0.1%			0.02%			0.1%	0.2%	0.1%	
हरियाणा	0(2)	0(1)	0(1)	—	—	—	—	—	0(1)	0(1)		0 (1)	0(3)	0 (1)
	0.8%	0.1%	0.03%						0.3%	0.2%		0.2%	0.2%	0.07%
हिमाचल प्रदेश	0(1)	—	0(1)	—	—	0(1)	—	0(1)				0 (1)	0(2)	0 (1)
	0.6%		0.8%			0.5%		1.0%				0.8%	0.8%	0.39%
कर्नाटक	0(2)	0(2)	—	0(1)	0(1)	—	0(1)	0(1)	0(1)	0(1)		0 (1)	0(2)	0 (1)
	1.6%	0.6%		0.2%	0.1%		0.2%	0.4%	0.04%	0.1%		0.1%	0.1%	0.05%
केरल	9(9)	2(11)	0(9)	7 (8)	1(10)	2(10)	3(9)	5(9)	6(9)	8(12)	12(13)	4 (14)	5+2*(10+5*)	1 (14+2*)
	24.6%	26.2%	20.3%	21.5%	22.3%	22.9%	20.7%	21.2%	21%	27.9%	31.5%	30.5%	21.6% (31.3%*)	25.83% (29.06%*)
मध्य प्रदेश	—	0(1)	—	0(1)	—	0(1)	0(1)	0(1)	0(2)	0(1)	0(1)	0 (1)	0(2)	0 (1)
		0.1%		0.1%		0.1%	0.02%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.03%	0.1%	0.03%
महाराष्ट्र	——	0(2)	3(3)	0(4)	0(2)	0(2)	1(2)	0(3)	0(3)	0(3)	0(3)	0 (2)	0(4)	0 (1)
		0.5%	3.6%	1.4%	1.5%	1.2%	1.3%	1.1%	0.6%	0.5%	0.7%	0.5%	0.4%	0.20%

	1967	1971	1977	1980	1984	1989	1991	1996	1998	1999	2004	2009	2014	2019
ओडिशा	___	0(1)	1(1)	0(1)	0(1)	1(1)	1(1)	0(1)	0(2)	0(2)		0 (1)	0(1)	0 (1)
		1.0%	2.0%	0.9%	1.8%	3.0%	2.1%	1.7%	0.4%	0.2%		0.4%	0.2%	0.1%
पंजाब	0(2)	0(3)	1(1)	0(1)		0(3)		0(3)	0(3)	0(1)	0(1)	0 (1)	0(3)	0 (1)
	1.9%	2.2%	4.9%	2.5%		3.9%		2.7%	1.1%	2.2%	1.8%	0.1%	0.1%	0.08%
राजस्थान	0(1)	0(3)	0(2)	0(1)	0(1)	1(1)	0(1)	0(1)	0(2)	0(1)	0(2)	0 (3)	0(3)	0 (3)
	1.0%	0.7%	0.4%	0.2%	0.2%	2.1%	0.7%	0.4%	1.3%	0.5%	0.5%	1.3%	0.3%	0.20%
सिक्किम							0(1)							
							2.9%							
तमिलनाडु	4(5)	0(6)	0(2)	0(3)	0(3)	0(4)	0(3)	0(7)	0(2)	1(2)	2(2)	1 (3)	0(9)	2 (2)
	6.9%	1.6%	1.6%	3.2%	2.8%	3.7%	2.5%	1.8%	0.6%	2.4%	2.9%	2.2%	0.5%	2.40%
तेलंगाना														0 (2)
														0.44%
त्रिपुरा	0(2)	2(2)	0(2)	2(2)	2(2)	0(2)	0(2)	2(2)	2(2)	2(2)	2(2)	2(2)	2(2)	0 (2)
	41.8%	43.5%	34.1%	47.5%	50.5%	41.7%	6.5%	52.4%	48.8%	56.2%	68.8%	61.7%	64%	17.31%
उत्तर प्रदेश	1(6)	0(3)	0(2)	0(1)	__	1(1)	0(3)	0(3)	0(2)	0(2)	0(2)	0 (2)	0(2)	
	1.2%	0.2%	0.1%	0.1%		0.5%	0.7%	0.7%	0.2%	0.03%	0.02%	0.01%	0.01%	
प. बंगाल	5(16)	20(38)	17(20)	28(31)	18(31)	27(31)	27(30)	23(31)	24(32)	21(32)	26(32)	9 (32)	2(32)	0 (31)
	15.7%	34.3%	26.2%	39.9%	35.9%	38.4%	35.2%	36.7%	35.4%	35.6%	38.6%	33.1%	22.7%	6.28%
अंडमान-निकोबार द्वीप	_____	___	__	0(1)	0(1)	0(1)	0(1)	0(1)	0(1)		0(1)	0 (1)	0(1)	
				20.3%	12.5%	30.5%	44.1%	14.3%	5.7%		2.7%	4.2%	0.9%	
चंडीगढ़	0(1)	___	___	__	__	__	___	0(1)						
	3.2%							2.3%						
दादर व नागर हवेली	0(1)	0(1)	___	___	___	0(1)	___				0(1)			
	20.0%	27.9%				10.8%					1.4%			
दमन व दीव	__	__	__	___	0(1)	__	___							
					0.4%									

	1967	1971	1977	1980	1984	1989	1991	1996	1998	1999	2004	2009	2014	2019
दिल्ली								0(1)						
								0.3%						
जम्मू व कश्मीर										0(1)	0(1)			
										1%	0.8%			
छत्तीसगढ़											0(1)	0 (1)	0(1)	
											0.2%	0.1%	0.1%	
झारखण्ड											0(1)	0 (2)	0(2)	0 (1)
											0.4%	0.5%	0.5%	0.24%
उत्तराखण्ड											0(1)	0 (1)	0(1)	0 (1)
											0.2%	0.2%	0.1%	0.14%
लक्षद्वीप												0 (1)	0(1)	0 (1)
												1.2%	1.1%	0.89%

नोट : कोष्ठकों में दी गई संख्या सीपीआई(एम) द्वारा लड़ी गई सीटें दिखलाती हैं। प्रतिशत में, कोष्ठकों में दी गई संख्याओं में पार्टी द्वारा समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों का प्रतिशत भी शामिल है।

टेबिल 2
17वीं लोकसभा चुनाव
सीपीआई(एम) द्वारा 2014 और 2019 में प्राप्त वोटों की तुलना

	राज्य	चुनाव क्षेत्र	2014			2019		
			वोट	%	स्थिति	वोट	%	स्थिति
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप		1,777	0.93	3rd			
		कुल	**1,777 (1 (1 सीट)**	**0.93**				
1	आंध्र प्रदेश	अरूकू	38,897	4.26	4th	नहीं लड़ी		
2		तिरूपति	11,168	0.92	4th	नहीं लड़ी		
3		नालगोंडा	54,423	4.57	4th	नहीं लड़ी		
4		भोनगीर	54,040	4.46	4th	नहीं लड़ी		
5		कुरनूल	नहीं लड़ी			18,919	1.6	5th
6		नेल्लोर	नहीं लड़ी			18,830	1.46	3rd
		कुल	**1,58,528 (6 सीटें)**	**0.33**		**37,749 (2 सीटें)**	**0.12**	
1.	असम	बारपेटा	27,575	2.28	5th	नहीं लड़ी		
2.		तेजपुर	24,910	2.54	5th	नहीं लड़ी		
3.		सिलचर	12,460	1.56	4th	नहीं लड़ी		
4.		कोकराझार (एसटी)	नहीं लड़ी			28,128	1.9	5th
5.		लखीमपुर *	नहीं लड़ी			12,809	1	5th
		कुल	**64,945 (3 सीटें)**	**0.43**		**40,937 (2 सीटें)**	**0.23**	

	राज्य	निर्वाचन क्षेत्र	2014			2019		
			वोट	%	स्थिति	वोट	%	स्थिति
1	बिहार	पश्चिम चंपारण	17,157	2.01	4th	नहीं लड़ी		
2		उजियारपुर	53,044	6.18	4th	27,577	2.85	3rd
3		दरभंगा	11,606	1.40	6th	नहीं लड़ी		
4		खगड़िया	24,490	2.73	4th	नहीं लड़ी		
		कुल	**1,06,297 (4 सीटें)**	**0.30**		**27,577 (1 सीट)**	**0.07**	
1	छत्तीसगढ़	सरगुजा	14,849	1.25				
		कुल	**14,849 (1 सीट)**	**0.12**		नहीं लड़ी		
1	गुजरात	दाहोद	28,958	3.21		नहीं लड़ी		
		कुल	**28,958 (1 सीट)**	**0.11**				
1	हरियाणा	सिरसा	11,194	0.88	6th	नहीं लड़ी		
2		हिसार	6,533	0.56	6th	9,150	0.78	6th
3		भिवानी-महेन्द्रगढ़	3,441	0.33	7th	नहीं लड़ी		
		कुल	**21,168 (3 सीटें)**	**0.18**		**9,150 (1 सीट)**	**0.07**	
1	हिमाचल प्रदेश	मण्डी	13,965	1.92	3rd	14,838	1.58	3rd
2		शिमला	11,434	1.56	4th	नहीं लड़ी		
		कुल	**25,399 (2 सीटें)**	**0.83**		**14,838 (1 सीट)**	**0.39**	
1	झारखण्ड	राजमहल	58,034	6.10	4th	35,586	3.4	3rd
2		रांची	10,178	0.97	7th	नहीं लड़ी		
		कुल	**68,212 (2 सीटें)**	**0.53**		**35,586 (1 सीट)**	**0.24**	

	राज्य	निर्वाचन क्षेत्र	2014			2019		
			वोट	%	स्थिति	वोट	%	स्थिति
1	कर्नाटक	चिकबल्लापुर	26,071	2.06	4th	18,648	1.34	4th
2		दक्षिण कन्नड़ा	9,394	0.78	4th	नहीं लड़ी		
		कुल	**35,465 (2 सीटें)**	**0.12**		**18,648 (1सीट)**	**0.05**	
1	केरल	कासरगोड	3,84,964	39.48	1st	4,34,523	39.5	2nd
2		कन्नूर	4,27,622	45.08	1st	4,35,182	41.29	2nd
3		वाडकर	4,13,173	43.03	2nd	4,42,092	41.49	2nd
4		कोझीकोड	3,80,732	40.36	2nd	4,08,219	37.93	2nd
5		मल्लपुरम	2,42,984	28.47	2nd	3,29,720	31.87	2nd
6		पालकट	4,12,897	45.35	1st	3,87,637	37.7	2nd
7	ा	अलथोर	4,11,808	44.34	1st	3,74,847	36.8	2nd
8		कोट्टम	3,70,879	42.18	2nd	3,50,821	36.24	2nd
9		अटिनगल	3,92,478	45.67	1st	3,42,748	34.11	2nd
10		अलपुज्जा	4,43,118	44.37	2nd	4,45,970	40.96	1st
		कुल	**38,80,655 (10 सीटें)**	**21.84**				
11		कोटायम	नहीं लड़ी			3,14,787	34.58	2nd
12		चालाकुट्टी	3,58,440 (Ind)	40.50	1st	3,41,170	34.45	2nd
13		अर्नाकुल्लम	2,66,794 (Ind)	31.35	2nd	3,22,110	33.3	2nd
14		पटनामिट्टा	3,02,651 (Ind)	34.74	2nd	3,36,684	32.8	2nd
		कुल				**52,66,510 (14सीटें)**	**25.83**	
15		इडुक्की	3,82,019 (Ind)	46.57	1st	3,27,440 (Ind)	35.62	2nd

	राज्य	निर्वाचन क्षेत्र	2014			2019		
			वोट	%	स्थिति	वोट	%	स्थिति
16		पोन्नानी	3,53,093 (Ind)	40.51	2nd	3,28,551 (Ind)	32.3	2nd
		ग्रांड टोटल	**55,53,652 (15 सीटें)**	**31.26**		**59,22,501 (16सीटें)**	**29.06**	
1	केंद्र शासित लक्षद्वीप	लक्षद्वीप	465	1.08	4th	420	0.89	4th
		कुल	**465 (1 सीट)**	**1.08**		**420 (1सीट)**	**0.89**	
1	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	10,297	1.04	5th	**नहीं लड़ी**		
2		रतलाम	6,078	0.56	8th	**नहीं लड़ी**		
3		रीवा	**नहीं लड़ी**			10,453	1.03	4th
		कुल	**16,375 (2 सीटें)**	**0.06**		**10,453 (1 सीट)**	**0.03**	
1	महाराष्ट्र	पालघर	76,890	7.74	3rd			
2		दिनथोरी	72,599	7.48	3rd	1,09,570	9.63	3rd
3		नासिक	17,154	1.83	5th	**नहीं लड़ी**		
4		हिंगोली	14,986	1.43	4th	**नहीं लड़ी**		
		कुल	**1,81,629 (4 सीटें)**	**0.38**		**1,09,570 (1 सीट)**	**0.20**	
1	ओडिशा	बहरामपुर	35,968	3.97	4th	**नहीं लड़ी**		
2		भुवनेश्वर	**नहीं लड़ी**			23,026	2.29	3rd
		कुल	**35,968 (1 सीट)**	**0.17**		**23,026 (1 सीट)**	**0.10**	
1	पंजाब	आनंदपुर साहेब	10,483	0.96	5th	10,665	0.99	5th
2		लुधियाना	4,167	0.38	8th	**नहीं लड़ी**		
3		संगरूर	3,315	0.30	10th	**नहीं लड़ी**		
		कुल	**17,965 (3 सीटें)**	**0.13**		**10,665 (1सीट)**	**0.08**	

	राज्य	निर्वाचन क्षेत्र	2014			2019		
			वोट	%	स्थिति	वोट	%	स्थिति
1	राजस्थान	सीकर	53,134	4.98	4th	31,462	2.37	3rd
2		चुरू	10,778	0.95	5th	25,090	1.89	3rd
3		गंगानगर	14,944	1.19	5th	नहीं लड़ी		
4		बीकानेर	नहीं लड़ी			8,997	0.82	5th
		कुल	**78,856 (4 सीटें)**	**0.29**		**65,549 (3 सीटें)**	**0.20**	
1	तमिलनाडु	कोयमबटूर	34,197	2.91	5th	5,71,150	45.66	1st
2		मदुराई	30,126	3.09	5th	4,47,075	44.00	1st
3		चेन्नैई उत्तर	23,751	2.61	5th	नहीं लड़ी		
4		विल्लुपरम	17,408	1.63	5th	नहीं लड़ी		
5		विरूद्धुनगर	20,157	1.99	5th	नहीं लड़ी		
6		कन्याकुमारी	35,284	3.56	5th	नहीं लड़ी		
7		दिंदीगुल	19,455	1.80	5th	नहीं लड़ी		
8		त्रिरूचिरापल्ली	17,039	1.72	5th	नहीं लड़ी		
9		तनजावूर	23,215	2.29	5th	नहीं लड़ी		
		कुल	**2,20,632 (9 सीटें)**	**0.55**		**10,18,225 (2 सीटें)**	**2.40**	
1	तेलंगाना	नालगोंडा	2014 चुनावों के समय तेलंगाना राज्य बना नहीं था			25,089	2.13	4th
2		खम्मम				57,102	5.01	3rd
		कुल				**82,191 (2 सीटें)**	**0.44**	
1	त्रिपुरा	त्रिपुरा पूर्वी	6,23,771	65.47	1st	2,00,963	19.22	3rd
2		त्रिपुरा पश्चिम	6,71,665	62.43	1st	1,71,826	15.51	3rd
		कुल	**12,95,436 (2 सीटें)**	**64.77**		**3,72,789 (2सीटें)**	**17.31**	
						त्रिपुरा (पश्चिम) मे चुनाव में खूब धांधली हुई		

	राज्य	निर्वाचन क्षेत्र	2014			2019		
			वोट	%	स्थिति	वोट	%	स्थिति
1	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	3,180	0.28%	4th	नहीं लड़ी		
2		वाराणसी	2,457	0.24%	6th			
		कुल	**5,637 (2 सीटें)**	**0.01**				
1	उत्तराखण्ड	टिहरी गढ़वाल	6,577	0.85	5th	6,626	0.76	4th
		कुल	**6,577 (1सीट)**	**0.15**		**6,626 (1 सीट)**	**0.14**	
1	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी (एससी)	4,25,167	32.60	2nd	76,166	5.07	3rd
2		दार्जलिंग	1,67,186	14.63	3rd	50,524	3.99	4th
3		रानीगँज	3,17,515	28.64	1st	1,82,035	14.25	3rd
4		मालदा उत्तर	3,22,904	27.76	2nd	50,401	3.72	4th
5		मालदा दक्षिण	2,09,480	19.17	3rd	नहीं लड़ी		
6		जहांगीरपुर	3,70,040	33.06	2nd	95,501	7.32	4th
7		मुर्शिदाबाद	4,26,947	33.13	1st	1,80,793	12.44	4th
8		कृष्णानगर	3,67,534	29.43	2nd	1,20,222	8.8	3rd
9		राणाघाट (एससी)	3,88,684	28.71	2nd	97,771	6.59	3rd
10		बनगांव	4,04,612	31.50	2nd	90,122	6.4	3rd
11		बैरकपुर	2,72,433	25.88	2nd	1,17,456	10.63	3rd
12		दमदम	3,28,310	28.96	2nd	1,67,590	13.91	3rd
13		मथुरापुर	4,91,494	38.66	2nd	92,417	6.59	3rd
14		डायमंड हार्बर	4,37,183	34.66	2nd	93,941	6.67	3rd
15		जादवपुर	4,59,041	36.01	2nd	3,02,264	21.04	3rd
16		कोलकाता दक्षिण	2,78,414	23.83	3rd	1,40,275	11.63	3rd
17		कोलकाता उत्तर	1,96,053	20.50	3rd	71,080	7.48	3rd
18		हावड़ा	2,91,505	25.89	2nd	1,05,547	8.64	3rd
19		उलूबेरिया	3,69,563	31.13	2nd	81,314	6.2	3rd

राज्य		निर्वाचन क्षेत्र	2014			2019		
			वोट	%	स्थिति	वोट	%	स्थिति
20		श्रीरामपुर	3,62,407	28.07	2nd	1,52,281	10.86	3rd
21		हुगली	4,25,228	31.48	2nd	1,21,588	8.34	3rd
22		आरामबाग	4,01,919	29.49	2nd	1,00,520	6.83	3rd
23		तामलुक	4,70,447	35.15	2nd	1,36,129	9.41	3rd
24		कांथी	4,47,259	34.61	2nd	76,185	5.35	3rd
25		जारगाम	3,26,621	25.97	2nd	75,680	5.38	3rd
26		बांकुरा	3,84,949	31.13	2nd	1,00,282	7.31	3rd
27		बीसनुपुर	4,29,185	33.74	2nd	1,02,615	7.22	3rd
28		बर्धमान पुरबा (एससी)	4,60,181	34.83	2nd	1,75,920	12.22	3rd
29		बर्धमान दुर्गापुर	4,47,190	33.58	2nd	1,61,329	11.26	3rd
30		आसनसोल	2,55,829	22.39	3rd	87,608	7.08	3rd
31		बोलपुर (एस सी)	3,94,581	30.23	2nd	91,964	6.29	3rd
32		बीरभूम	3,93,305	30.82	2nd	96,763	6.68	3rd
		कुल	**1,17,23,166 (32 सीटें)**	**22.96**		**35,94,283 (31 सीटें)**	**6.28%**	

अखिल भारतीय

2014 में कुल सीटें लड़ी : 98 (5 स्वतंत्र उम्मीदवारों समेत)

2014 में कुल वोट प्राप्त : 1,96,49,770 (स्वतंत्र उम्मीदवारों समेत)

2014 में प्राप्त वोटों का प्रतिशत : 3.5 (स्वतंत्र उम्मीदवारों समेत)

2014 में प्राप्त वोटों का प्रतिशत (बिना स्वतंत्र उम्मीदवारों के 3.28)

2019 में कुल सीटें लड़ीं : 71(2 स्वतंत्र उम्मीदवारों समेत)

2019 में कुल प्राप्त वोट : 1,14,00,783 (2 स्वतंत्र उम्मीदवारों समेत)

टेबिल -3
विधानसभा चुनावों में सीपीआई(एम) का प्रदर्शन

आंध्र प्रदेश

	निर्वाचन क्षेत्र	वोट	प्रतिशत
1.	कुरूपम	8,605	6.01
2.	अरकु	10,445	6.63
3.	रामपाचोद्दारम	18,182	9.01
4.	उंडी	24,737	13.29
5.	विजयवाड़ा	29,333	16.48
6.	शान्तनुतालापदु	5,988	3.32
7.	कुरनुल	3,771	2.47
	कुल	**1,01,071**	**0.32%**

ओडिशा

	निर्वाचन क्षेत्र	वोट	प्रतिशत
1.	बोनाई (जीती)	59,939	34.67
2.	नीलगिरि	3,394	2.16
3.	मोरोडा	2,570	1.43
4.	पालाहारा	1,775	1.29
5.	रनपुर	2,441	1.63
	कुल	**70,119**	**0.30**

प. बंगाल उपचुनाव

	निर्वाचन क्षेत्र	वोट	प्रतिशत
1.	कृष्णागंज	11,646	5.27
2.	उल्लूबेरिया पूरबा	21,339	11.97
3.	इस्लामपुर	5,128	3.51
4.	हबीबपुर	10,076	5.56
5.	बटूटपारा	3,589	3.59
6.	दार्जलिंग	2,087	1.46
	कुल	**53,865**	**4.12**